देश को नए दशक में आत्मनिर्भर बनाने वाला है बजट: वित्त मंत्री

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विशेष साक्षात्कार...पेज-22-25

वर्ष: 01, अंक:16

16 से 28 फरवरी 2021, नि:शुल्क

न्यू इंडिया समाचार

आत्मनिर्भरता का आम बजट

साहसिक और सुधारवादी दृष्टिकोण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे भारत का ये बजट इस दशक की शुरुआत की एक मजबूत नींव रखेगा

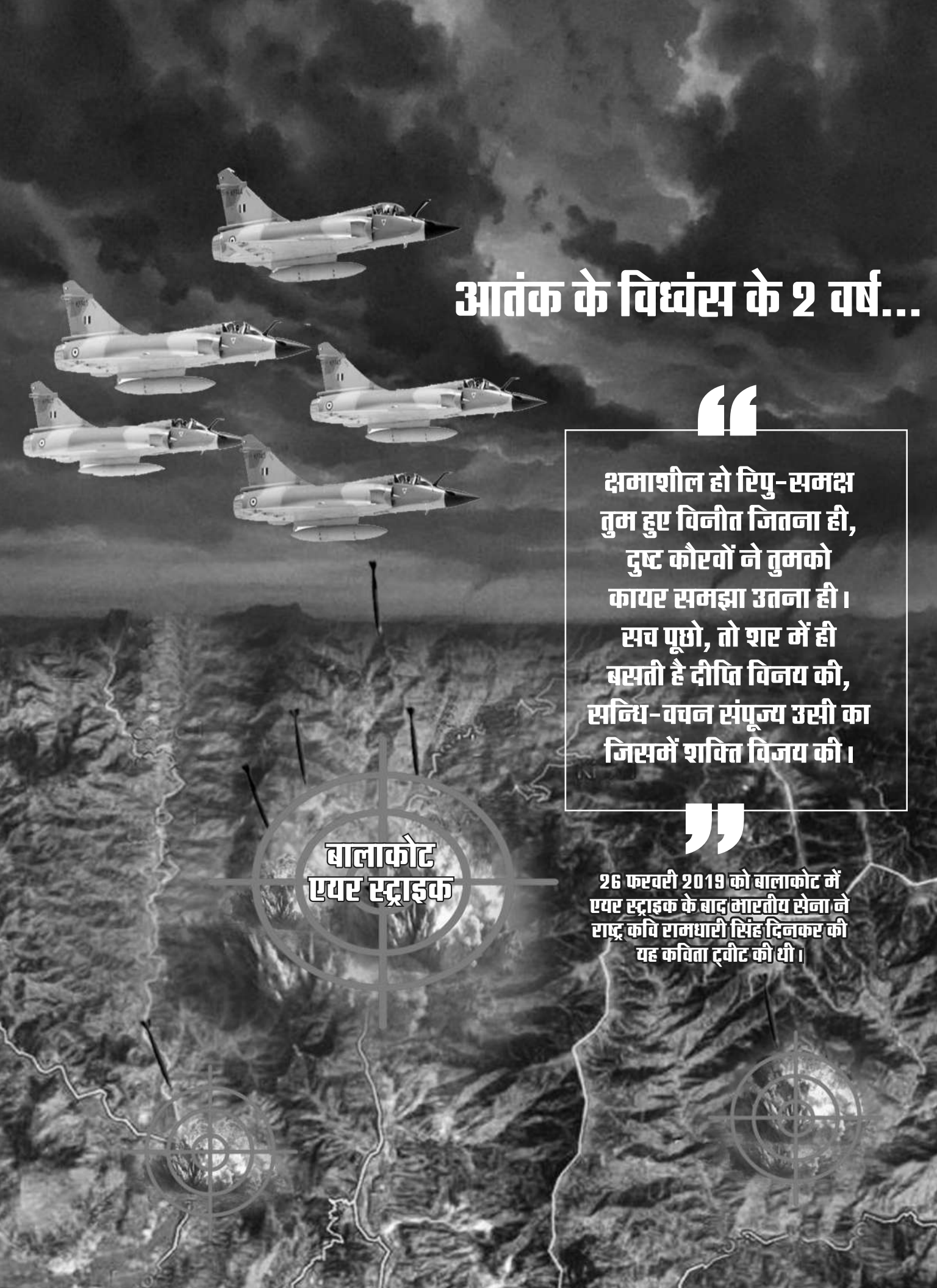
आतंक के विध्वंस के 2 वर्ष...
क्षमाशील हो रिपु-समक्ष
तुम हुए विनीत जितना ही,
दुष्ट कौरवों ने तुमको
कायर समझा उतना ही।
सच पूछो, तो शर में ही
बसती है दीप्ति विनय की,
सन्धि-वचन संपूज्य उसी का
जिसमें शक्ति विजय की।
बालाकोट
एयर स्ट्राइक
26 फरवरी 2019 को बालाकोट में
एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय सेना ने
राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की
यह कविता ट्वीट की थी।

न्यू इंडिया
समाचार
वर्ष: 01, अंक: 16 | 16 से 28 फरवरी 2021

संपादक
कुलदीप सिंह धतवालिया,
प्रधान महानिदेशक,
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

सलाहकार संपादक
संतोष कुमार
विनोद कुमार

सहायक सलाहकार संपादक
विभोर शर्मा

प्रकाशक और मुद्रक:
सत्येन्द्र प्रकाश,
महानिदेशक, बीओसी
(ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन)

मुद्रण: जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड, बी-278, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-20

संपर्क: ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन,सूचना भवन, द्वितीय तल,नई दिल्ली- 110003
ईमेल- **response-nis@pib.gov.in**

डिजाइनर
श्याम शंकर तिवारी

आर. एन. आई. नंबर
DELHIN/2020/78812

अंदर के पन्नों पर...

आत्मनिर्भरता का बजट

आवरण कथा

अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने के लिए आधारभूत ढांचे और स्वास्थ क्षेत्र में भारी निवेश को घोषणा, साथ में वित्त मंत्री का साक्षात्कार। पेज 8-25

फ्लैगशिप योजना...

रुर्बन मिशन: गांवों की आत्मा, शहरों सा विकास

पेज 34-35

पद्म सम्मान

न्यू इंडिया में अब सम्मानित होने लगे गुमनाम नायक

न्यू इंडिया में बदली सोच तो अब सामने आने लगीं गुमनाम नायकों के संघर्ष की प्रेरणादायक कहानियां
पेज 36-39

समाचार-सार
देश की प्रमुख खबरें। पेज 4-5

गुरुदेव; चिंतन, दर्शन और परिश्रम का साकार रूप
राष्ट्रगान देने वाले गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को नमन। पेज 6-7

चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार भारत
विश्व आर्थिक मंच के शिखर से प्रधानमंत्री का संबोधन। पेज 26-27

वैक्सीन मैत्री अब दुनिया के लिए 'मेड इन इंडिया'
सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के साथ दुनिया का ध्यान। पेज 28-29

सशक्त भारत और सोनार बांग्ला की प्रेरणा नेताजी
नेताजी के जन्मदिन पर कोलकाता पहुंचे प्रधानमंत्री। पेज 32

दुनिया के अनुकूल होगा कौशल विकास का तीसरा चरण
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत। पेज 33

आत्मनिर्भर कृषि के लिए अब जागा एक नया भरोसा
सम्मान निधि के 2 साल और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के 6 साल। पेज 40-41

जम्मू-कश्मीर: पनबिजली परियोजना का इंतजार खत्म
कैबिनेट की बैठक में हुए अहम फैसले। पेज 42

आत्मनिर्भरता के रास्ते मिली सफलता
कहानी बदलते भारत की। पेज 43

"भारत में बना टीका आत्म गौरव का प्रतीक"
मन की बात, 20वीं कड़ी, 31 दिसंबर। पेज 44

सरदार पटेल की प्रेरणा स्थली से जुड़ा देश

रेल कनेक्टिविटी से बदलेगी केवड़िया की सूरत, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के अलग-अलग हिस्सों से जोड़ने के लिए 8 नई ट्रेनों की शुरुआत। पेज 30-31

संपादक की कलम से...

सादर नमस्कार।

नया वर्ष, नया दशक, कोरोना महामारी की पहाड़ जैसी चुनौतियों को पार कर प्रगति के पथ पर अग्रसर नए भारत का बजट। इन चंद शब्दों के जरिए आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने वाले भारत का संदेश साफ है कि चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, न हम रुकेंगे और न देश रुकेगा। 'न्यू इंडिया समाचार' का ताजा अंक नए भारत के इसी संकल्प को समर्पित है। कोरोना महामारी के बाद यह देश का पहला बजट है लेकिन सरकार ने इस आपदा में अपने लोगों पर कोई बोझ बढ़ाए बिना ऐसे भारत की नींव रख दी है जो अपने पैरों पर खड़ा होगा। आत्मनिर्भरता का यह आम बजट इस अंक की आवरण कथा बनी है जो देश को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर लेकर आगे बढ़ते हुए हर नागरिक की प्रगति को सुनिश्चित करेगा।

स्वास्थ्य पहली बार किसी सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है क्योंकि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही स्वस्थ सोच के साथ देश को महान बनाने के सपने बुन भी सकता है, गढ़ भी सकता है। इस बार का आम बजट अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि इसमें गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, उद्यमी समेत सभी वर्ग का समावेश है। छह मजबूत स्तंभों पर आधारित यह आम बजट आधुनिकता और नए सुधार लाने के लिए एक वैक्सीन की तरह ही काम करने वाला है।

ऐसे ही स्नेह और विश्वास के साथ आप अपना विचार और सुझाव हमें लिखते रहिए

पता- ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन,
सूचना भवन, द्वितीय तल
नई दिल्ली- 110003
ईमेल- **response-nis@pib.gov.in**

कुलदीप

(कुलदीप सिंह धतवालिया)

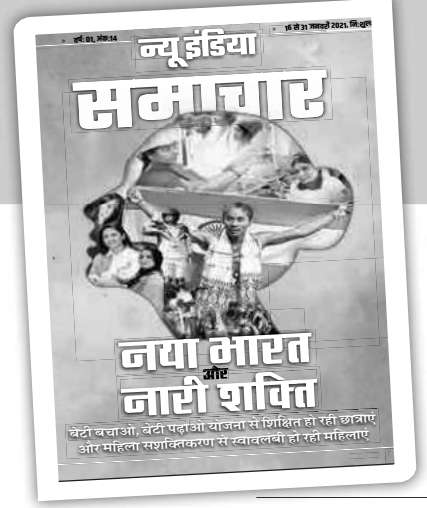

आपकी बात...

न्यू इंडिया समाचार का नया अंक से प्राप्त हुआ। प्रेषित करने के लिए धन्यवाद। इस अंक में प्रकाशित सामग्री बड़े सुझबूझ से चयनित की गई हैं। अंक में प्रकाशित लेख ज्ञानवर्धक हैं। देश के बढ़ते कदमों पर गर्व करने के लिए प्रेरित करते हैं। नए भारत के केंद्र में नारी शक्ति लेख पढ़कर लगा कि अब यदि भारत को विश्व के अग्रणी देशों के साथ खड़ा होना है तो महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में आगे लाने व आने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री द्वारा किसानों से संवाद अत्यंत आवश्यक पहलू है। अन्नदाता की नारजगी देश के हित में नहीं होगी। पराक्रमगाथा के अंतर्गत देश के पहले परमवीर मेजर सोमनाथ शर्मा के संबंध में जानकारी से ज्ञान में वृद्धि हुई है। न्यू इंडिया समाचार के अगले अंक की प्रतीक्षा रहेगी। **b.balaji@midhani-india.in**

आपकी पहल स्वागत योग्य है। इस अंक में आप कुछ निचले स्तर की सशक्त महिलाओं की कहानी भी दे सकते है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी साहस नही छोड़ा और जिसे मीडिया नही दिखाता है।

mamtamittal593@gmail.com

न्यू इंडिया पत्रिका का अंक बहुत ही ज्ञानवर्धक और नई सूचनाओं से भरपूर था। हमे ऐसे ही आगे भी आपके द्वारा देश दुनिया की खबरें प्राप्त होती रहे इन्हीं कामनाओं के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।

guptamanoj432111@gmail.com

इस पत्रिका में नारी शक्ति और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर उनसे संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के सरकार के फैसले के बारे में जानकारी मिली। नारी का सम्मान होना जरुरी है।

गणेश रानबा वाघमारे
ganeshwaghmare2013@gmail.com

न्यू इंडिया समाचार के माध्यम से हमें नई योजना और नये प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मिली। साथ ही बहुत सारी अन्य जानकारी मिली। आपका प्रयास अतुलनीय है। आशा है कि आप आगे भी इसी तरह का प्रयास करते रहेंगे।

vpinki27@gmail.com

आपने नारी शक्ति पर अंक निकाला। आपने भारत की नारी के बारे में जानकारी पूरी विश्व भर में पहुंचाया, इसके लिए आपका एक बार तुम बहुत बहुत धन्यवाद।

vikramsinghvalera@gmail.com

न्यू इंडिया समाचार का 40 पृष्ठीय जनवरी 2021 अंक 14 प्राप्त हुआ। पर्यटन, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, स्टार्टअप, कृषि सुधार और महानायक पर विशेष सामग्री पठनीय है। आकर्षक और सुंदर साज-सज्जा के साथ प्रस्तुत न्यू इंडिया समाचार के प्रकाशन के लिए बहुत बधाई।

आशीष 'अनमोल'
ashish35.srivastava@yahoo.in

न्यू इण्डिया समाचार पत्रिका देश के नोजवानों के लिए प्रेरणादायक है। इसमें छपे लेख और समाचार देश हित में लोगों को एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। नारी शक्ति देश में सबसे करगर कदम साबित हो रहा है। नारी अब अबला नहीं है। न्यू इण्डिया पत्रिका निशुल्क मिलना सराहनीय है।

surag.bureau2004@gmail.com

मिलिट्री कॉलेज ने किया आरओवी और माइन डिटेक्टर का निर्माण, करेगा सैनिकों की मदद

मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने अभियान के दौरान दुश्मनों की स्थिति का पता लगाने के लिए एक वाहन का निर्माण किया है। यह वाहन दूर से संचालित होगा। यह एक आरओवी और माइन डिटेक्टर उपकरण है, जिसे कैप्टन राज प्रसाद ने बनाया है। यह उपकरण खुद ही विस्फोट कर दुश्मन को मार गिरा सकता है। यह उन सुरंगों की पहचान भी करेगा, जहां खतरा है या विस्फोटक सामग्री बिछाई गई है। रिमोट ऑपरेटिड व्हीकल (आरओवी) में मेटल डिटेक्टर की सुविधा भी दी गई है जो लैंड माइन्स को खोजने में सैनिकों की मदद करेगा। इसमें एक ल्युमिनेटिंग स्प्रे की सुविधा भी दी गई है जो उन जगहों पर निशान लगाएगा, जहां खतरा है या जहां खतरा होने की संभावना है। अभी तक यह आरओवी और माइन डिटेक्टर वाहन ट्रायल मोड में है। परीक्षण के बाद इन्हें सेना को उपयोग के लिए दे दिया जाएगा।

डिजिटल दुकानदारी अपनाएं, कैशबैक का फायदा उठाएं

कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वालों के लिए शुरू की गई पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना में अब डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत रेहड़ी-पटरी वाले छोटे दुकानदारों को 4 जनवरी से 22 जनवरी तक डिजिटल दुकानदारी के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इनमें दुकानदारों को डिजिटल लेन-देन के फायदे बताए गए जिसमें कहा गया कि एक बार सीखने पर जिंदगी भर लाभ उठा सकते हैं। कहीं धोखा नहीं खाएंगे। पीएम स्वनिधि में छोटे दुकानदारों को कारोबार के लिए 10 हजार रुपए का लोन मिलता है जिसमें 50 लाख से अधिक दुकानदारों को लाभ देने का लक्ष्य है। डिजिटल दुकानदारी के तहत दुकानदारों को महीने में पहले 50 लेनदेन पर 50 रुपए कैशबैक आएगा तो उसके बाद के 50 लेनदेन पर 25 रुपए मिलेंगे और फिर उसके बाद के 100 लेनदेन पर 25 रुपए का कैशबैक आएगा। महीने में 100 रुपए का अधिकतम कैशबैक मिलेगा। बैंकों ने यह भी साफ किया है कि डिजिटल लेनदेन से रिकार्ड अच्छा होगा, लोन में भी आसानी होगी। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत ब्याज, सब्सिडी एवं डिजिटल कैशबैक दुकानदारों के खाते में इंडियन बैंक पहुंचाएगा।

अब स्टार्टअप इंडिया के लिए 1000 करोड़ रुपये का नया फंड

वर्ष 2014 में देश का मिजाज बदलने के साथ ही केंद्र सरकार ने मील के पत्थर के रूप में कुछ ऐसे क्षेत्रों में नई योजनाओं की सौगात दी, जिनके बारे में इससे पहले कभी सोचा ही नहीं गया था। इनोवेटिव सोच के साथ कुछ कर गुजरने की चाहत लिए युवा उद्यमियों के लिए 16 जनवरी 2016 को 'स्टार्टअप इंडिया' के रूप में ऐसी ही एक नई शुरुआत की गई थी। स्टार्टअप इंडिया की सफलता के 5 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक और नई शुरुआत का एलान किया है। इसके तहत 1000 करोड़ रुपये की नए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की शुरुआत की गई है। ताकि नए स्टार्टअप को ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके। इस अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में 25 से अधिक देशों के 200 से ज्यादा वक्ता शामिल हुए।

#startupindia

सफलता के 5 साल

"पहले अगर कोई युवा स्टार्टअप शुरू करता था तो लोग कहते कि तुम नौकरी क्यों नहीं करते। स्टार्टअप क्यों? लेकिन अब लोग कहते हैं कि नौकरी ठीक है लेकिन स्टार्टअप क्यों नहीं शुरू करते। —नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री"

भारत का पहला गोबर पेंट लॉन्च; सबसे सस्ता और इको-फ्रेंडली

भारतीय सभ्यता और संस्कृति में गाय का अहम योगदान है। हिंदु धर्म में तीज-त्योहारों में गाय के गोबर से लीपने का विशेष महत्व है। लेकिन अब आप अपने घरों में भी गोबर से बना पेंट उपयोग कर पाएंगे। वो भी मनचाहे रंग के अनुसार। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग(केवीआईसी) ने गाय के गोबर से बना हुआ पेंट 'खादी प्राकृतिक पेंट' के नाम से लॉन्च किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने इसे लॉन्च किया। यह पेंट इको फ्रेंडली, नॉन टॉक्सिक के अलावा एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और वॉशेबल भी होगा। पेंट में गोबर की गंध नहीं होगी। इस पेंट को भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रमाणित भी किया है। यह पेंट दो तरह का होगा- डिस्टेंपर पेंट और इमल्शन पेंट। गोबर से बने इस पेंट में लेड, मरकरी, कैडमियम, क्रोमियम जैसी हानिकारक धातुएं नहीं हैं। दीवार पर पेंट करने के बाद यह सिर्फ चार घंटे में सूख जाएगा। इस पेंट में आप अपनी जरूरत के हिसाब से रंग भी मिला सकते हैं। फिलहाल इसकी पैकिंग 2 लीटर से लेकर 30 लीटर तक तैयार की गई है। यह पेंट आम पेंट के मुकाबले सस्ता (डिस्टेंपर केवल 120 रुपये/लीटर और इमल्शन केवल 225 रुपये/लीटर) होगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इसकी स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे गोबर की खपत बढ़ेगी। साथ ही किसानों की आय भी बढ़ेगी। सरकार के अनुमान के हिसाब से यह किसानों या गौशालाओं को प्रत्येक वर्ष प्रति पशु पर 30,000 रुपए की अतिरिक्त आय देगा।

सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने प्रधानमंत्री

भारत के प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र के रूप में विख्यात गुजरात के सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट का अध्यक्ष सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। सोमनाथ मंदिर की व्यवस्था और संचालन का कार्य सोमनाथ ट्रस्ट के अधीन किया जाता है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री केंशुभाई पटेल ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, लेकिन उनके निधन के बाद से यह पद रिक्त था। गुजरात पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत बने श्री सोमनाथ धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट में 8 सदस्य होते हैं। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव प्रवीण लाहेरी इस ट्रस्ट के सदस्य हैं। वहीं, अंबुजा न्योतिया समूह के हर्षवर्धन न्योतिया और वेरावल से संस्कृत के रिटायर्ड प्रोफेसर जेडी परमार भी ट्रस्ट के गैर राजनीतिक सदस्य हैं। सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाए जाने पर जामनगर के शाही परिवार ने प्रधानमंत्री को पगड़ी भेंट की। पीएम मोदी ने यही पगड़ी 72वें गणतंत्र दिवस के समारोह में पहनी।

एक सप्ताह में 534 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, यानी एक दिन में 76 किमी से ज्यादा

भारत में बेहतरीन सड़क मार्ग केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए रोज नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। 8 जनवरी से शुरू हुए एक सप्ताह में इस दौरान देश में कुल 534किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया। यानी एक दिन में औसत 76 किमी से ज्यादा। अप्रैल 2020 से 15 जनवरी2021 के दौरान देश में कुल 8,169 किमी नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया है। यानी प्रतिदिन औसत 28.16 किमी। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान पूरे में देश में लॉकडाउन की वजह से करीब 2 महीने निर्माण कार्य को रोक दिया गया था।

GoI CALENDAR APP

इसे गूगल प्ले स्टोर और आईओएस पर डाउनलोड कर सकते हैं।

गूगल प्ले स्टोर लिंक

https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.calendar

आईओएस लिंक

https://apps.apple.com/in/app/goi-calendar/id1546365594

https://goicalendar.gov.in/

“जॉदि तोर डाक शुने केऊ न आशे तोबे एकला चलो रे”

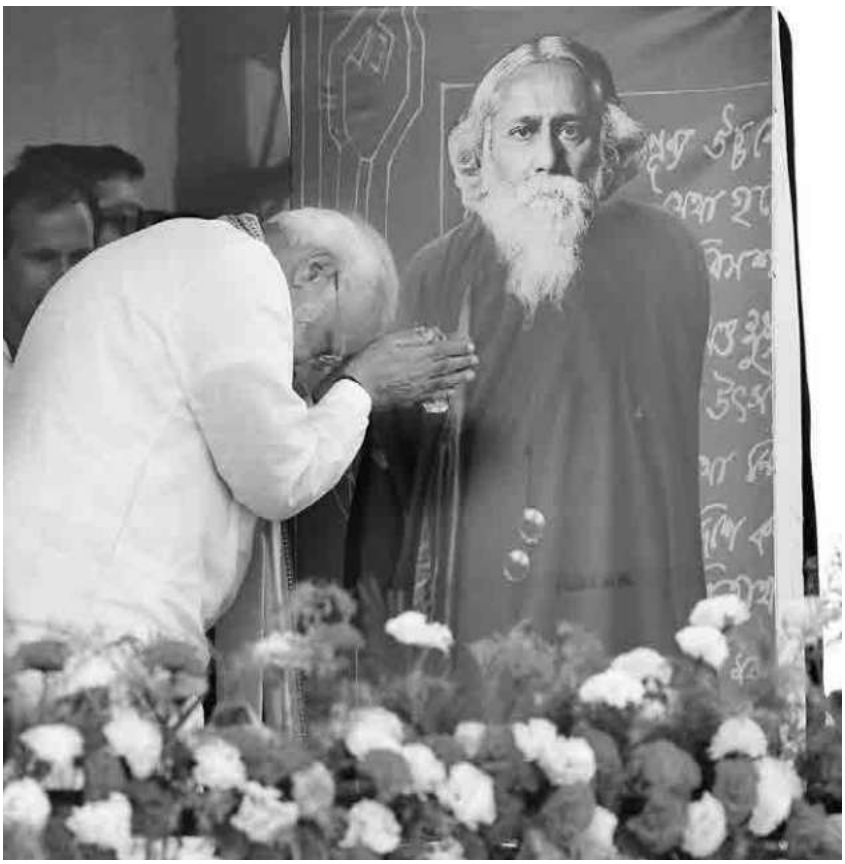

गीतांजलि, राजर्षि, चोखेर बालि, गोरा...साहित्य के संसार में ये चमकते दस्तावेज रवींद्रनाथ टैगोर की ही देन हैं। लेकिन टैगोर के महान व्यक्तित्व का दायरा दरअसल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तभी तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने खुद उन्हें सबसे पहले ‘गुरुदेव’ कहा था। इस वर्ष जब भारत 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, हमें जन-गण-मन के रूप में राष्ट्रगान देने वाले गुरुदेव को नमन करना चाहिए। भारत ही नहीं बांग्लादेश को भी आमार-सोनार-बांग्ला के रूप में राष्ट्रगान गुरुदेव की ही देन है...

कोलकाता के जोरसांको ठाकुरबाड़ी में 7 मई 1861 में देवेन्द्र नाथ टैगोर के घर जन्मे रवींद्रनाथ टैगोर कवि और उपन्यासकार के साथ नाटककार, दार्शनिक और चित्रकार भी थे। उनके एक भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस के पहले अफसर थे।

बचपन से ही साहित्य में झुकाव...

मात्र 8 वर्ष की आयु में अपनी पहली कविता लिखने वाले गुरुदेव ने 16 वर्ष की उम्र में नियमित तौर पर कविता और नाटक लिखना आरंभ कर दिया। टैगोर ने बैरिस्टर बनने की चाहत में 1878 में इंग्लैंड के ब्रिजटोन पब्लिक स्कूल में नाम दर्ज कराया। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया लेकिन 1880 में बिना डिग्री हासिल किए ही वापस आ गए। भारत आकर गुरुदेव ने फिर से लिखने का काम शुरू किया। 1901 में टैगोर ने पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शांतिनिकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की। जहां उन्होंने भारत और पश्चिमी परंपराओं के सर्वश्रेष्ठ को मिलाने का प्रयास किया। वह विद्यालय में ही स्थायी रूप से रहने लगे और 1921 में यह विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया।

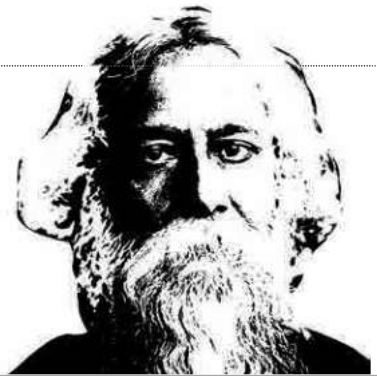

"मैंने स्वप्न देखा कि जीवन आनंद है। मैं जागा और पाया कि जीवन सेवा है। मैंने सेवा की और पाया कि सेवा में ही आनंद है। – रवींद्रनाथ टैगोर

दुनिया ने पहली बार माना भारतीय प्रतिभा का लोहा

जीवन के 51 वर्षों तक गुरुदेव की सारी उपलब्धियां केवल कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित रहीं। समुद्री मार्ग से भारत से इंग्लैंड जाते समय उन्होंने अपने कविता संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद करना प्रारंभ किया, वो भी समय काटने की गरज से उन्होंने एक नोटबुक में अपने हाथ से गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया। लंदन में टैगोर के अंग्रेज मित्र विख्यात चित्रकार रोथेंस्टिन को जब यह पता चला कि गीतांजलि को स्वयं रवींद्रनाथ टैगोर ने अनुवादित किया है तो उन्होंने उसे पढ़ने की इच्छा जाहिर की। रोथेंस्टिन ने अपने मित्र प्रसिद्ध कवि डब्ल्यू .बी. यीट्स को गीतांजलि पढ़ने के लिए दी। यीट्स ने स्वयं गीतांजलि के अंग्रेजी के मूल संस्करण की प्रस्तावना लिखी।

लंदन के साहित्यिक गलियारों में इस किताब की खूब सराहना हुई। भारत की साहित्य रचना का स्वाद दुनिया ने पहली बार चखा। गीतांजलि के प्रकाशित होने के एक साल बाद सन् 1913 में रवींद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्का र से सम्मा नित किया गया। साहित्य नोबेल सम्मान पाने वाले टैगोर पहले गैर यूरोपीय थे।

बापू को दी महात्मा की उपाधि...

टैगोर गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे। लेकिन वे उनसे राष्ट्रीयता, देशभक्ति जैसे विषयों पर अलग राय रखते थे। हर विषय में टैगोर का दृष्टिकोण परंपरावादी कम और तर्कसंगत ज्यादा हुआ करता था, जिसका संबंध विश्व कल्याण से होता था। टैगोर ने ही गांधीजी को 'महात्मा' की उपाधि दी थी। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनीं। भारत के साथ बांग्लादेश का राष्ट्रगान गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। श्रीलंका का राष्ट्रगान 'श्रीलंका माता' लिखने वाले आनंद समाराकून भी गुरुदेव के ही शिष्य थे।

साहित्य की हर विधा में रचना...

साहित्य की शायद ही ऐसी कोई विधा है, जिनमें गुरुदेव की रचना न हो - गान, कविता, उपन्यास, कथा, नाटक, प्रबंध, शिल्पकला, चित्रकला, सभी विधाओं में उनकी रचनाएं विश्वविख्यात हैं। टैगोर ने करीब 2,230 गीतों की रचना की। टैगोर के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता।

जब अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी...

अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज्य करो की नीति ने हमें भारत-पाकिस्तान दिए लेकिन यह उनका पहला प्रयास नहीं था। इससे पहले भी अंग्रेज़ बंगाल विभाजन में यही फॉर्मूला अपना चुके थे। वर्ष था 1905, दिन 16 अक्टूबर। बंगाल विभाजन के विरोध में गुरुदेव ने जुलूस का आह्वान किया। इसका उद्देश्य था राह में जो मिले उसे राखी बांधना। यह गुरुदेव द्वारा हिन्दू-मुस्लिम एकता का आह्वान था। पूरे देश में बंगभंग आंदोलन की शुरुआत हो गई। यही नहीं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में टैगोर ने अंग्रेजों से मिली 'सर' की उपाधि भी लौटा दी थी।

विश्वभारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, "वेद से विवेकानंद तक भारत के चिंतन की धारा गुरुदेव के राष्ट्रवाद के चिंतन में भी मुखर थी और ये धारा अंतर्मुखी नहीं थी। वो भारत को विश्व के अन्य देशों से अलग रखने वाली नहीं थी। उनका विजन था कि जो भारत में सर्वश्रेष्ठ है, उससे विश्व को लाभ हो और जो दुनिया में अच्छा है, भारत उससे भी सीखे।" ●

आत्मनिर्भरता

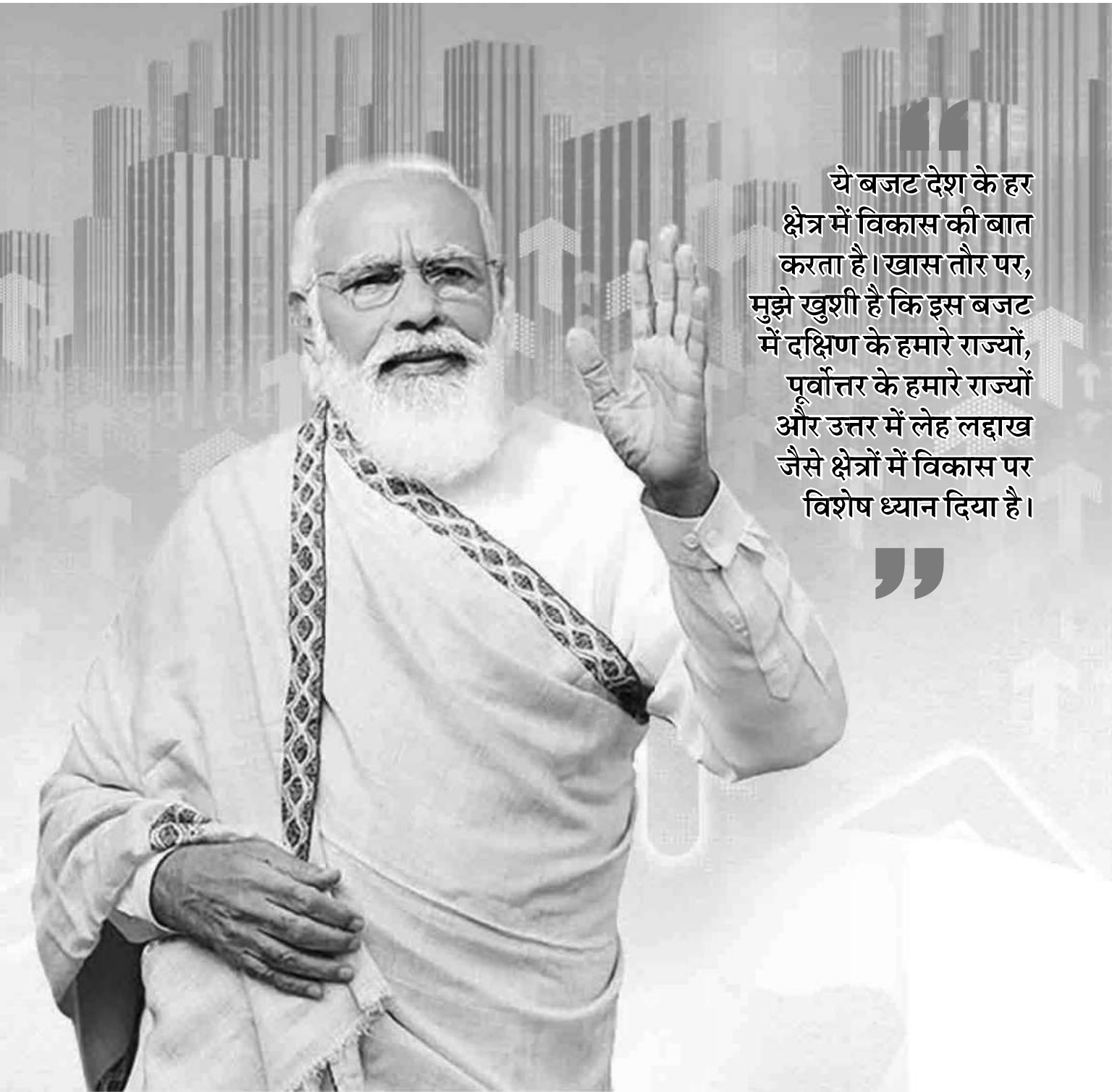

"ये बजट देश के हर क्षेत्र में विकास की बात करता है। खास तौर पर, मुझे खुशी है कि इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्यों, पूर्वोत्तर के हमारे राज्यों और उत्तर में लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया है।"

का बजट

अपनी क्षमताओं और कौशल पर भरोसा करने वाले 130 करोड़ लोगों की अभिव्यक्ति का आधार बना है यह आम बजट। केंद्र सरकार ने आम जनता पर कोई बोझ डाले बिना गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला, स्वास्थ्य सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा की दिशा में व्यावहारिक बजट पेश किया है। इससे अगले 3-4 साल में देश की अर्थव्यवस्था को न सिर्फ गति मिलेगी, बल्कि समग्र दृष्टिकोण और दीर्घकालिक सोच के साथ पेश किया गया बजट सुधारों की निरंतरता के लिए एक वैक्सीन की तरह काम करेगा और आत्मविश्वास से लबरेज देश बनेगा आत्मनिर्भर...

स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे में अब तक के सबसे बड़े निवेश की घोषणा, इसी से निकलेगा आत्मनिर्भरता का रास्ता

यह आपका, हमारा और आत्मनिर्भरता का बजट है। देश की उम्मीदों का साकार करने वाला है। आम बजट मौजूदा सरकार के लिए वित्तीय जरूरतों को पूरा करने का साधन भर नहीं, बल्कि हर वित्तीय प्रावधान को अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक नियत समय में पहुंचाकर पं. दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपनों को पूरा करने वाला है। यही वजह है कि कोरोना जैसी असाधारण विपरीत परिस्थियों के बीच भी सरकार ने आम जनता पर किसी तरह का बोझ नहीं डाला है, लेकिन देश को अपने पैरों पर खड़ा करने का ऐसा खाका खींचा है जिसमें 'राष्ट्र प्रथम' की सोच के साथ किसानों की आय को दोगुना करना, सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वस्थ भारत, युवाओं के लिए नए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तीकरण और नीतिगत सुधारों में

निरंतरता के साथ हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने की संकल्प शक्ति है। 21वीं सदी के नए दशक का पहला आम बजट अब तक के इतिहास का संभवतया पहला बजट होगा जब सरकार ने अपने राजस्व की पूर्ति के लिए लोगों पर बोझ डाले बिना खर्च के लिए राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए विनिवेश और अन्य स्रोतों का सहारा लिया है। जबकि कोरोना आपदा की वजह से देश की अर्थव्यवस्था नकारात्मक आंकड़े में चली गई थी। लेकिन जन-भागीदारी और नेतृत्व की दीर्घकालिक सोच ने इस आपदा को अवसर में बदल दिया। अब आम बजट के जरिए "सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास" के मंत्र को सुनिश्चित करते हुए सरकार ने 6 महत्वपूर्ण स्तंभों के साथ बजट को दिल्ली से ब्लॉक तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ 'जान भी, जहान भी' के सपने को पूरा करने की दिशा में क्रांतिकारी कदम बढ़ाया है।

नई स्वास्थ्य क्रांति

आम आदमी की आकांक्षाओं के अनुरूप आम बजट को नई स्वास्थ्य क्रांति का जनक कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। स्वास्थ्य कभी भी देश की राजनीति का केंद्र नहीं रहा, जबकि देश में आम आदमी सबसे अधिक इसी मद पर खर्च करता रहा है और इस बोझ की वजह से हर साल 8 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे जाने को मजबूर हो जाया करते थे। लेकिन मौजूदा सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही सबको स्वास्थ्य का हक दिलाने की दिशा में दुनिया की सबसे बड़ी पीएम-जय आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत 5 लाख रु. के मुफ्त इलाज की सुविधा दी। अब आम बजट में सीधे 137 फीसदी की

पहली बार डिजिटल बजट...वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में जहां भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने पर जो दिया तो खुद भी इस बात का ध्यान रखा। यह पहली बार था जब किसी वित्त मंत्री ने अपना पूरा बजट भाषण टैब में देखकर पढ़ा। इसकी कोई कॉपी प्रिंट नहीं की गई।

बढ़ोतरी कर संदेश दिया है कि स्वस्थ भारत ही दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। बजट में न सिर्फ इलाज बल्कि बीमारी से बचाने के उपाय और तृतीयक स्तर की बड़ी बीमारियों के इलाज वाली सुविधा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए 'प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना' का एलान किया गया है। स्वास्थ्य से जुड़ी स्वच्छता, पोषण अभियान का दूसरा चरण शुरू करने, स्वच्छ जल, वायु प्रदूषण और सभी तक कोरोना व अन्य वैक्सीन पहुंचाने का भी बड़ा लक्ष्य रखा गया है। यह सिर्फ सोच नहीं, बल्कि इस पर अमल के लिए बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खासा जोर दिया गया है।

“ ये बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केन्द्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस, दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे – जान भी, जहान भी।
– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री ”

“ ये बजट आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है, जिसमें देश के हर नागरिक की प्रगति शामिल है। ये बजट, इस दशक की शुरुआत की एक मजबूत नींव रखने वाला है। ”

आत्मनिर्भर भारत के 6 स्तंभ

स्वास्थ्य और कल्याण
वास्तविक और वित्तीय पूंजी, और बुनियादी ढांचा
आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास
मानव पूंजी में नवजीवन का संचार
इनोवेशन- रिसर्च एंड डेवलपमेंट
न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन

इंफ्रास्ट्रक्चर से अग्रणी बनेगा देश

मूलभूत ढांचे के विकास के बिना कोई भी देश विश्व में अग्रणी नहीं बन सकता। जीवन को गति देने की इसी सोच के साथ सरकार ने आम बजट में 1.18 लाख करोड़ रु. का प्रावधान किया है, जिससे तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम समेत देश भर में सड़क निर्माण का अभूतपूर्व ढांचा तैयार होगा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन परियोजना का विस्तार करते हुए इसमें 7400 परियोजनाएं शामिल की गई हैं। रेलवे विकास को गति प्रदान करता है, ऐसे में बजट में रेलवे का दायरा बढ़ाने, यात्रा की सुगमता, सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय रेल परियोजना- 2030 बनाई गई है। छोटे-छोटे शहरों को मेट्रो से जोड़ना हो या फिर हरित ऊर्जा की दिशा में कदम या फिर अगले 3 वर्षों में 100 से अधिक शहरों में गैस पाइपलाइन पहुंचाने का लक्ष्य, विकास को नई दिशा देगा। सरकार अब भविष्य के ऊर्जा स्रोत के लिए हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की शुरुआत करने जा रही है। विनिर्माण क्षेत्र में भारत को विश्व चैंपियन बनाने की दिशा में अगले पांच वर्षों के लिए 1.97 लाख करोड़ की पीएलआई योजना से युवाओं के लिए नई नौकरियां सृजित होंगी।

गांव, किसान, मजदूर से समग्र विकास

इस आम बजट के दिल में गांव, मजदूर और किसान हैं जो ग्रामीण भारत के विकास के केंद्र बिंदु हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए स्वामीनाथ आयोग की सिफारिशों के मुताबिक लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुनिश्चित करना हो या फिर किसान क्रेडिट कार्ड, मत्स्य संपदा योजना और सूक्ष्म सिंचाई के प्रावधान, बजट की आत्मा है। किसानों को आसानी से ऋण मिलने की सुविधा, मंडियों को कानूनी रुप से मजबूत करना, कृषि इंफ्रा फंड से मदद की विशेष व्यवस्था की गई है। गांवों के विकास में स्वामित्व योजना का विस्तार, गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, प्रवासी मजदूरों के लिए एक देश-एक राशन कार्ड को देश भर में लागू करने का लक्ष्य, लेबर कोड से मजदूरों को न्याय और सौगात देना, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना को अनुकूल बनाया गया है। अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले एमएसएमई सेक्टर का बजट दोगुना कर सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती दी है।

शिक्षा और अनुसंधान से तरक्की

शिक्षा किसी भी समाज के विकास का मूल आधार है। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत का आम बजट जड़ों को सींचने और सभी तक शिक्षा और शोध को पहुंचाने की दिशा में अहम भागीदार बनेगा। बजट में 15 हजार से अधिक स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने, 100 नए सैनिक स्कूल, अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण को ध्यान में रखते हुए जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूल खोलने, इस वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को बढ़ाने, कौशल विकास को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में बजट ने नई दिशा प्रदान की है। लेकिन इनोवेशन के बिना दुनिया ठहर जाती है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इनोवेशन के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात कही गई थी। प्रधानमंत्री की इस सोच के तहत बजट में 5 साल के लिए 50 हजार करोड़ रु. का विशेष फंड बनाया गया है। न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के सिद्धांत के तहत सरकार ने आम बजट 75 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट दी है। सुधारों की गति को आगे बढ़ाते हुए कोरोना महामारी के बाद पेश किया गया देश का पहला आम बजट सही मायने में हर साल की औपचारिकता नहीं, बल्कि एक संकल्प और दृष्टिकोण है- आत्मनिर्भर भारत का। ●

कितना पैसा आया

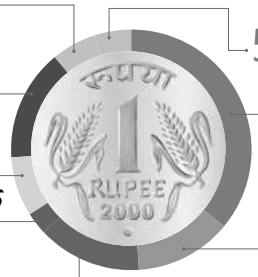

- 6 पै. कर भिन्न राजस्व
- 15 पै. माल एवं सेवा कर
- 8 पै. केंद्रीय उत्पाद शुल्क
- 3 पै. सीमा शुल्क
- 14 पै. आयकर
- 13 पै. निगम कर
- 36 पै. उधार व अन्य देनदारी
- 5 पै. ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां

कहां खर्च हुआ

- 10 पै. अन्य व्यय
- 5 पै. पेंशन
- 16 पै. करों और शुल्कों में राज्यो का हिस्सा
- 10 पै. वित्त आयोग और अन्य अंतरण
- 9 पै. आर्थिक सहायता
- 8 पै. रक्षा
- 20 पै. ब्याज आदायगी
- 14 पै. केंद्र की योजनाएं
- 9 पै. केंद्र प्रयोजित योजनाएं

एक नज़र में बजट

राजस्व प्राप्तियां
आंकडे करोड़ में

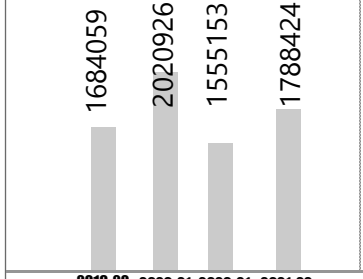

पूंजीगत प्राप्तियां
आंकडे करोड़ में

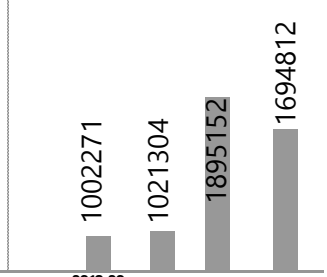

राजस्व व्यय
आंकडे करोड़ में

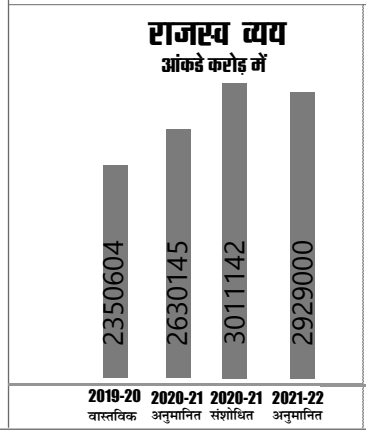

पूंजी व्यय
आंकडे करोड़ में

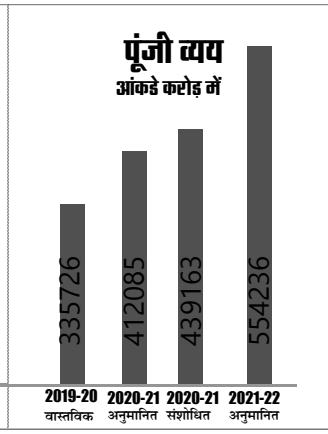

आपदा के बावजूद कोई अतिरिक्त कर नहीं

कोरोना जैसी आपदा के बीच पहली बार सरकार ने पेट्रोल डीजल समेत कई वस्तुओं पर कृषि उपकर बढ़ाया तो कस्टम व एक्साइज ड्यूटी कम कर, इसका बोझ आम आदमी पर नहीं पड़ने दिया। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ पर कोई नया कर भी नहीं लगा।

आत्मनिर्भर भारत अभियान अर्थव्यवस्था का एक पड़ाव भर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे चर्चित शब्द बन गया है। ऑक्सफोर्ड ने आत्मनिर्भरता को वर्ष 2020 का सबसे चर्चित हिंदी शब्द चुना है। इसी आत्मनिर्भता की झलक नए भारत के बजट में मिली है।

कोरोना जैसी महामारी से जब पूरी दुनिया जूझ रही हो तब केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य के साथ न केवल आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं बल्कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाले कई फैसले किए हैं। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है पर **75 साल से ज्यादा उम्र वाले नागरिकों को अब रिटर्न नहीं देना होगा।** इसके साथ ही रिटर्न दाखिल करने को आसान बनाने समेत इनकम टैक्स एक्ट में 77 संशोधन किए गए हैं। जैसे- महत्वपूर्ण मामलों रिअसेसमेंट की समय सीमा अब 6 से घटाकर 3 साल की गई है। खर्च बढ़ाने के साथ मांग में सुधार के लिए रणनीतिक विनिवेशन पर जोर दिया गया है। वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा 9.5% रहने का अनुमान है। केंद्र सरकार ने इसे वर्ष 2025-26 तक 4.5% लाने का लक्ष्य तय किया है। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालने का भी एलान किया है। एनपीए पर एसेट मैनेजमेंट कंपनी का भी गठन किया जाएगा।

राजकोषीय घाटा

जीडीपी का प्रतिशत घाटा की प्रवृत्ति

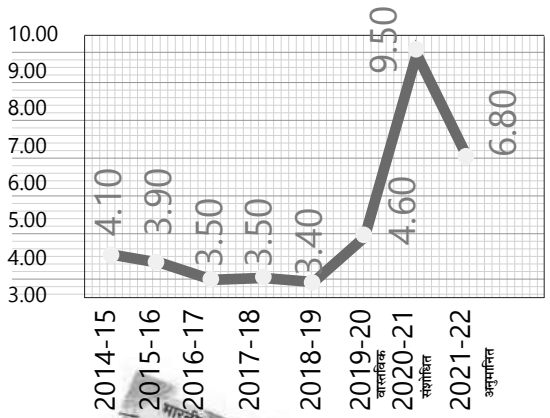

जीएसटी संग्रहण राजस्व प्राप्ति का सबसे स्रोत है

12,00,000
करोड़ रुपये का कर्ज जुटायगी सरकार वित्त वर्ष 2021-22 दौरान

34,83,000
करोड़ रुपये सरकार का व्यय रहने का अनुमान है अगले वर्ष

1500 करोड़ से छोटे शहरों में डिजिटल भुगतान को मिलेगा बढ़ावा

5 नई योजनाएं बदलेंगी भारत की सूरत

जल जीवन मिशन (शहरी)

गांवों के बाद शहरों में हर घर में नल कनेक्शन का लक्ष्य।

2.86 करोड़ घरों को नल कनेक्शन के साथ सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में समान जल आपूर्ति और 500 अमृत शहरों में तरल कचरा प्रबंधन उपलब्ध कराना है। 5 साल में 2,87,000 करोड़ रु. खर्च कर हासिल होगा लक्ष्य।

स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत

स्वास्थ्य मंत्रालय का बजट 10% से ज्यादा बढ़ाया। पेयजल और स्वच्छता को साथ जोड़कर स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर परिणाम का लक्ष्य। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरु की गई। इसमें 6 साल में 64,180 करोड़ रुपये स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कुल 1,41,678 करोड़ रुपये की धनराशि के आवंटन के साथ 5 साल की अवधि में कार्यान्वित किया जाएगा।

स्वच्छ वायु

वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से पार पाने के लिए इस बजट में 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले 42 शहरी केन्द्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है।

स्क्रैप नीति

पुराने और जर्जर वाहनों के निपटारे के लिए पहली बार देश में नई स्क्रैप नीति की घोषणा की गई है। निजी गाड़ियों की एक्सपायरी 20 वर्ष और कमर्शियल की 15 वर्ष निर्धारित। इससे पर्यावरण में सुधार होगा। 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश के साथ 50 हजार नए रोजगार पैदा होंगे।

मिशन पोषण 2.0

कुपोषण से लड़ाई के लिए 112 जिलों में शुरु किया जाएगा। पोषण अभियान और अतिरिक्त पोषण कार्यक्रम का विलय किया गया।

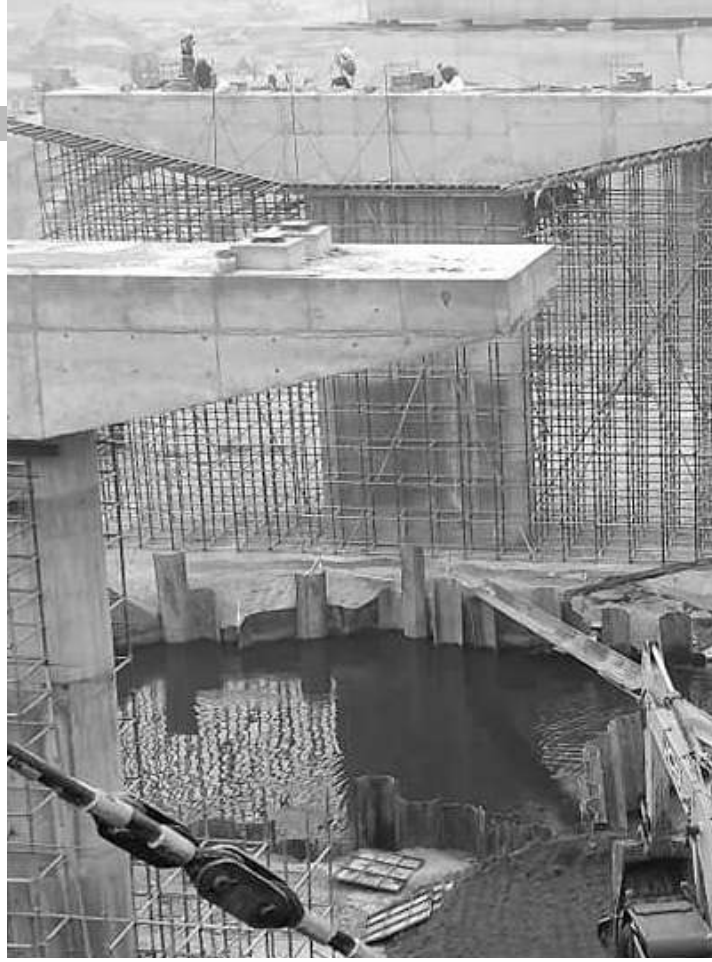

इंफ्रास्ट्रक्चर

विकास की नई इबारत की तैयारी

बुनियादी ढांचे में विस्तार और राजमार्ग, रेल, मेट्रो के साथ सार्वजनिक परिवहन को नई गति देने की तैयारी ताकि अर्थव्यवस्था को मिले और तेज रफ्तार

कोरोना काल में मंद रही अर्थव्यवस्था अब 'वी' आकार में उबर रही है। इसे और तेज रफ्तार देने के लिए सर्वाधिक फोकस बुनियादी ढांचे के विकास पर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सीधे निवेश के नियमों को आसान बनाकर रोजगार को बढ़ाने के लिए नए आर्थिक गलियारे बनाए जाएंगे। इसके लिए 3 साल में 5 लाख करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। 20,000 करोड़ रुपये की लागत से डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी।

सड़क परिवहन: सड़क विस्तार को नई रफ्तार

5.35 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली भारतमाला परियोजना के तहत 3.3 लाख करोड़ रुपये की लागत से 13000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी सड़कों के ठेके पहले ही दिए जा चुके हैं, जिनमें से 3800 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण हो चुका है। मार्च 2022 तक सरकार 8500 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए भी ठेके दे देगी। इसके साथ ही सरकार 11000 किलोमीटर और लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर का निर्माण पूरा कर लेगी। असम में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण पर 34,000 करोड़, प.बंगाल में 25 हजार करोड़, तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

भारतीय रेल: भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयारी

1,10,055 करोड़ रु. के रिकॉर्ड आवंटन से भारतीय रेलवे की सूरत बदलने की तैयारी है। रेलवे को भविष्य के हिसाब से तैयार करने के लिए 'राष्ट्रीय रेल योजना-2030' की शुरुआत की गई है। मेक इन इंडिया के साथ उद्योग जगत को सहूलियत के लिए माल ढुलाई भाड़ा कम किया जा रहा है। जून 2022 तक वेस्टर्न व ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर की शुरुआत हो जाएगी।

ग्रामीण भारत

40 हजार करोड़ रु. गांवों में इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए

86% लोग एक देश-एक राशन कार्ड के तहत कवर

पब्लिक ट्रांसपोर्ट

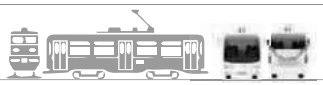

18 हजार करोड़ रुपये दिए गए पब्लिक बस सुविधा लिए

भारतीय रेलवे

100% इलेक्ट्रिफिकेशन रेल लाइनों का 2023 तक

1.10 लाख करोड़ रुपए रेलवे को दिए गए हैं। इसमें 1.07 लाख करोड़ रुपए नए प्रोजेक्ट के लिए हैं।

नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन स्कीम में 565 नए के साथ अब 7,400 प्रोजेक्ट हो गए हैं।

मेट्रो के साथ मेट्रो नियो की शुरुआत

सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं के विस्तार के लिए 18000 करोड़ रुपये की लागत से एक नई योजना शुरू की जाएगी। चेन्नई में 180 किमी लंबी मेट्रो परियोजना के लिए 63 हजार करोड़ व कोच्चि में 1900 करोड़ रु. में 11 किमी मेट्रो परियोजना का हिस्सा बनेगा। छोटे और मंझोले शहरों में दो नई तकनीक 'मेट्रोलाइट' और 'मेट्रो नियो' लागू की जाएंगी।

बिजली: अब अपनी मर्जी से चुनें अपनी कंपनी

बिजली वितरण में सुधार के लिए 3,05,984 करोड़ रु. से नई योजना की शुरुआत। बजट के साथ सुधारों पर आधारित और प्रदर्शन से संबद्ध विद्युत वितरण क्षेत्र योजना पेश करने का प्रस्ताव किया गया है। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एक क्षेत्र में कम से कम दो बिजली कंपनियां को मंजूरी मिलेगी।

जल जीवन मिशन(शहरी) की शुरुआत

हर घर को नल कनेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में जल जीवन मिशन(ग्रामीण) योजना की शुरुआत की गई थी। इसी तर्ज पर अब जल जीवन मिशन(शहरी) योजना को शुरू किया जा रहा है। इसके तहत 2.86 करोड़ घरों में नल कनेक्शन दिया जाएगा। 500 अमृत शहरों में तरल कचरा प्रबंधन किया जाएगा। शहरों में स्वच्छता के लिए शहरी स्वच्छ मिशन वर्ष 2021 से 2026 तक चलाया जाएगा।

पेट्रोलियम-प्राकृतिक गैस: उज्ज्वला में 1 करोड़ नए परिवार

उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों को इसका लाभ दिया जाएगा। अगले तीन वर्ष में शहरी गैस वितरण नेटवर्क में 100 अतिरिक्त शहरों को जोड़ा जाएगा। जम्मू और कश्मीर में एक गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी।

किफायती आवास के लिए नई घोषणाएं

सबको किफायती घर मिल सके इसके लिए अफॉर्डेबल हाउसिंग और अफॉर्डेबल रेंटल प्रोजेक्ट में काम करने वाले बिल्डरों के लिए रियायतों की अवधि एक साल और बढ़ा दी है। किफायती घर खरीदने वालों को 1.5 लाख ब्याज की अतिरिक्त कर छूट को एक साल के लिए बढ़ाया गया है। इस फैसले से जहां रियल एस्टेट सेक्टर को मदद मिलेगी, वहीं लोगों का अपना घर का सपना भी पूरा हो सकेगा। ●

जल ही जीवन

2.86 करोड़ घरों में नल से पानी मिलेगा अगले पांच साल में

₹2.87 लाख करोड़ शहरी जल जीवन मिशन के लिए

अब होगा सफर आसान

8500 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट शुरू होंगे अगले साल तक

1.18 लाख करोड़ रुपये सड़क मंत्रालय को

7 नई बंदरगाह परियोजना की शुरुआत पीपीपी मोड पर 2000 करोड़ रु. की लागत से होगी।

स्वस्थ भारत-खुशहाल भारत

ब्लॉक से शहरों तक सुधार

भारत का अभी तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बजट, पिछले वर्ष के मुकाबले 137 फीसदी की बढ़ोतरी की, 2 लाख 23 हजार 846 करोड़ रुपये दिए

इस समय जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रही है, यह केंद्र सरकार की आम आदमी के प्रति प्रतिबद्धता का ही नतीजा है कि पहली बार स्वास्थ्य क्षेत्र को भारत के आम बजट में इतनी बड़ी हिस्सेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार स्वास्थ्य और देखभाल, आत्मनिर्भर भारत के 6 स्तंभों में सबसे प्रमुख स्तंभ है, इसी का असर है कि पिछली बार जो स्वास्थ्य बजट 94,452 करोड़ रुपये का था, उसमें इस बार 137 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।

कोरोना महामारी से मिली सीख के आधार पर केंद्र सरकार ने संक्रामक बीमारियों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए जांच और उपचार का मजबूत ढांचा खड़ा करने पर जोर दिया है। ऐसी बीमारियों की जांच,सूचना और निगरानी के लिए ब्लॉक से लेकर जिला व राष्ट्रीय स्तर तक प्रयोगशालाओं का नेटवर्क खड़ा किया जाएगा। स्वास्थ्य पोर्टल के दायरे में सभी राज्य आएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से चार क्षेत्रीय वायरोलॉजी लैब की स्थापना की जाएगी। अभी तक देश में केवल पुणे में ही एक मात्र ऐसी लैब है। 32 हवाई अड्डों, 11 बंदरगाह, 7 सीमा चौकियों पर

ऐसे सुधरेगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर

₹ 35,000
करोड़ का फंड कोरोना वैक्सीन के लिए अलग से रखा गया

3382
ब्लॉक में लोक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना

28,812
वेलनेस सेंटरों की स्थापना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ्य भारत योजना के तहत की जाएगी।

11 राज्यों के सभी जिलों में एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की शुरुआत होगी।

पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं व महामारी की पहचान और जाचं के लिए ढांचा तैयार किया जाएगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। पहली बार देशभर में नौनिहालों को लगेगा निमोनिया का टीका

कोरोना की दो और वैक्सीन की तैयारी

कोरोना वैक्सीन के लिए 35000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री के अनुसार जरूरत पड़ी तो और फंड आवंटित किया जाएगा। अभी भारत में दो वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है। जल्द ही टीकाकरण अभियान में दो और वैक्सीन को शामिल किया जा सकता है। दुनिया के 100 से ज्यादा देश वैक्सीन के लिए भारत की ओर देख रहे हैं।

64,180 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ्य भारत योजना के तहत अगले 6 साल में

4 वायरस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी। अभी केवल 1 इंस्टीट्यूट पुणे में है। 9 बायो सुरक्षा स्तर-3 लैब बनेगी

05 शाखाएं बनेंगी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की

20 महानगरों में यूनिट स्थापित होंगी।

बढ़ा आयुष का बजट

848 करोड़ रुपये अधिक बजट मिला इस बार आयुष मंत्रालय को। बीते वित्त वर्ष में 2122 करोड़ रुपये दिए गए थे।

मौजूद स्वास्थ्य केंद्रों को और मजबूत बनाया जाएगा। देश में 2 मोबाइल और 15 आपातकालीन ऑपरेशन केंद्रों की शुरुआत की जाएगी।

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की शुरुआत

बजट प्रावधानों के मुताबिक, नए वित्तीय साल में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की जाएगी। यह स्कीम मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के अलावा होगी। इस मद में 64180 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत देश में हेल्थ सेक्टर में बुनियादी सुविधाएं जुटाई जाएंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ ही प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के इंतजाम किए जाएंगे।

निमोनिया के टीके से बचेगी 50 हजार बच्चों की जान

आम बजट में इस बार निमोनिया के स्वदेशी टीके न्यूमोकोकल के लिए देशभर में अभियान चलाने की घोषणा की गई है। इसके जरिए 50 हजार बच्चों की जान बचाई जा सकेगी। अभी केवल 5 राज्यों में ही यह टीकाकरण अभियान चल रहा है।●

उद्योग

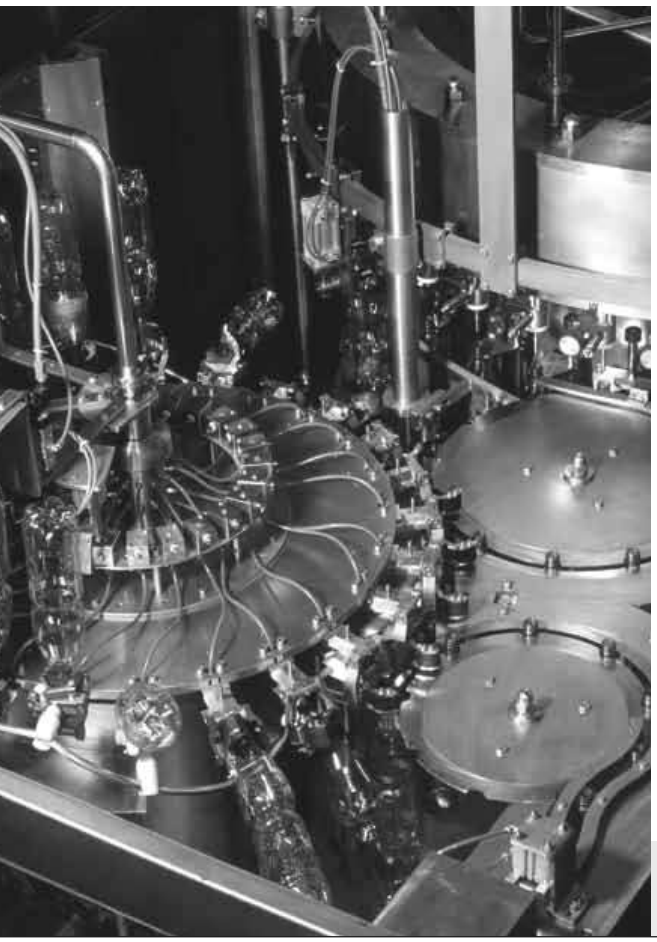

एमएसएमई के सहारे पूरा होगा संकल्प

अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए 63 करोड़ सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को 15700 करोड़ रु., यह पहले के मुकाबले दोगुना

05 करोड़ नई नौकरियां पैदा करना लक्ष्य

7 नए टेक्सटाइल मेगा पार्क बनाए जाएंगे। ताकि कपड़ा उद्योग को ताकत मिले

13 क्षेत्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) की घोषणा।

74% **विदेशी निवेश हो सकेगा बीमा क्षेत्र में, पहले यह 49% था।**

भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाला एमएसएमई सेक्टर कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यही कारण है वित्त मंत्री सीतारमण ने इस बार आम बजट में सबसे ज्यादा राहत इसी सेक्टर को दी है। अब पूंजी के आधार पर छोटी कंपनियों की परिभाषा बदली जाएगी। 50 लाख रुपये से बढ़ाकर छोटी कंपनियों के पूंजीगत आधार को 2 करोड़ रुपये किया जाएगा। इससे 2 लाख कंपनियों को फायदा होगा। इससे पहले जून 2020 में भी एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन किया गया था। आम बजट में इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मशीन लर्निंग पर जोर दिया जाएगा। केंद्र सरकार का लक्ष्य आर्थिक विकास में एमएसएमई के योगदान को 30% से बढ़ाकर 40% करना है।

जीएसटी प्रणाली और आसान होगी, उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आयात होने वाली वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाया।

निर्यात में इस सेक्टर की भागीदारी 48 से बढ़ाकर 60% करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना में 50 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। साथ ही, निवेशकों की सुरक्षा के लिए पहली बार इस्वेटमेंट चार्टर लाने की योजना है। इनोवेशन की नई पहचान बने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए दी गईं रियायतों को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। लोहा और इससे संबंधित कच्चे माल पर कस्टम शुल्क घटाया गया है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में मैन्युफेक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा निगम को 1 हजार करोड़ और अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसियों को 1500 करोड़ रु. दिए जाएंगे।

शिक्षा

शोध और कौशल विकास को बढ़ावा

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर जोर, कौशल आधारित पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कई कार्यक्रम होंगे शुरू

50,000 करोड़ रु. दिए गए राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान की स्थापना के लिए

750 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी आदिवासी क्षेत्रों में।

15,000 स्कूलों को नई शिक्षा नीति के तहत सुदृढ़ बनाया जाएगा। इनकी गुणवत्ता बढ़ाए जाने पर जोर।

34 साल बाद मिली नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर बजट में विशेष जोर दिया गया है। इसके अनुसार जहां स्कूलों में पढ़ाई के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा, तो वहीं कौशल आधारित पढ़ाई पर अब सरकार का फोकस है। लेह में नया केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए उच्च शिक्षा आयोग के गठन का प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की भी शुरुआत की जाएगी। इसका काम होगा सरकारी दस्तावेजों को प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाना।

पढ़ाई पूरी करने, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन-डिप्लोमा करने वाले छात्रों को अप्रेंटिसशिप योजना के तहत ट्रेनिंग।

750 नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए बजट राशि 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 38 करोड़ रुपये तक कर दी गई है। वहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी छात्रों के लिए स्कूलों को 48 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अनूसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जारी रहेगी। इसके लिए वित्तीय मदद बढ़ाई जा रही है। अगले 6 साल के लिए 35,219 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जिससे देश के करीब 4 करोड़ एससी स्टूडेंट्स को 10वीं के बाद शिक्षा जारी रखने में मदद दी जाएगी। युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए जापान के साथ ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाया जाएगा। ●

खेती-बाड़ी

आधारभूत ढांचा सुधारने की पहल

अभी तक फसलों की लागत की डेढ़ गुना एमएसपी दी, वर्ष 2022 तक आय दोगुनी करने के लिए 16 अहम फैसले

शुल्क बढ़ाया कपास आयात पर, घरेलू किसानों को होगा फायदा

16.5 लाख करोड़ रु. किया गया कृषि कर्ज का दायरा।

5 नए फिशिंग हब बनाए जाएंगे मछली उत्पादन को बढ़ावा देने कि लिए

हमेशा से कृषि क्षेत्र केंद्र सरकार की प्राथमिकता में रहा है। यही कारण है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-22 के आम बजट में एक बार फिर किसान की आय दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य को दोहराया। इसके लिए कृषि से जुड़ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे- स्टोरेज, प्रसंस्करण यूनिट, ढुलाई आदि के ढांचे में सुधार के उपाय बताए गए हैं। सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कृषि आधारभूत ढांचा कोष से एपीएमसी मंडियों का विकास किया जाएगा। वर्ष 2021-22 के लिए बजट में कृषि क्षेत्र को 1.48 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कृषि ऋण को 10% तक बढ़ाने के साथ ही पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए लोन बढ़ाने की घोषणा भी की गई है। एफपीओ को बढ़ावा देकर छोटे किसानों की आय बढ़ाई जाएगी। सूक्ष्म सिचांई के लिए 5 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए गए हैं। फलों और सब्जियों की ढुलाई के लिए शुरू की गई ऑपरेशन ग्रीन योजना में अब 22 और उत्पाद शामिल होंगे। 40 हजार करोड़ रुपये गांवो में आधारभूत ढांचे के निर्माण में खर्च होंगे तो असम और प.बंगाल के चाय मजदूरों के विकास के लिए 1 हजार करोड़ रुपये भी दिए गए हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफार्म ई-नाम से 1 हजार नई मंडियां जोड़ी जाएंगी। ●

ग्रामीण क्षेत्र में विकास के साथ मछली पालन और बागवानी पर ध्यान। पीएम स्वामित्व योजना अब पूरे देश में लागू होगी।

रक्षा क्षेत्र

आधुनिकीकरण की राह आसान

वर्ष 2014 के मुकाबले अब दोगुना हुआ हमारा रक्षा बजट, आत्मनिर्भर अभियान के तहत स्वदेशी मैन्युफेक्चरिंग बढ़ाने की तैयारी

4.78 लाख करोड़ रु. हुआ रक्षा बजट, 2014 में यह 2.29 लाख करोड़ रु. था।

18.75% बजट में बढ़ोतरी सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए।

100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे देशभर में पीपीपी मोड पर

इस साल के बजट में रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा क्षेत्र के पूंजीगत व्यय (नए साजो-सामान की खरीद के लिए इस्तेमाल बजट) में 18.75 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। पिछले 15 सालों के दौरान रक्षा क्षेत्र में नए साजो-सामान की खरीद के लिए इस्तेमाल बजट में यह अब तक की सर्वाधिक वृद्धि है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा सेवाओं और अन्य संगठनों/विभागों (रक्षा क्षेत्र की पेंशन को छोड़कर) के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 3,62,345.62 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 24,792.62 करोड़ रुपये अधिक है। परिचालन संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गैर-वेतन राजस्व के तहत आवंटन को बढ़ाकर 54,624.67 करोड़ रुपये किया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में यह 6 प्रतिशत अधिक है। डीआरडीओ के लिए पूंजीगत आवंटन को बढ़ाकर 11,375.50 करोड़ रुपये किया गया है, जो वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 8 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 8.5 प्रतिशत अधिक है। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के लिए आवंटित बजट को बढ़ाकर 6004.08 करोड़ किया गया है, जो वित्त वर्ष 2020-21 के मुकाबले 7.48 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले 14.49 प्रतिशत अधिक है। ●

रक्षा क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ का बजट बढ़ाया। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती देने की पहल।

देश को नए दशक में आत्मनिर्भर बनाने वाला है बजट: वित्त मंत्री

आत्मनिर्भरता अब सिर्फ भारत के 130 करोड़ देशवासियों का आंदोलन ही नहीं, दुनिया का सबसे चर्चित शब्द बन गया है। आज़ाद भारत के इतिहास में यह पहला ऐसा बजट है जो एक विजन के साथ देश को नए दशक में आत्मनिर्भर बनाने वाला है। ये आम बजट क्यों सबसे अलग है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू इंडिया समाचार के सलाहकार संपादक संतोष कुमार के सवालों के जवाब दिए...

"कहा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने में पांच साल लगेगा। हां, परियोजना पूरा होने में पांच साल लगेगा लेकिन नौकरी तो तुरंत मिलेगी। उसकी वजह से अर्थव्यवस्था में तुरंत तेजी आएगी। यही है मुख्य मुद्दा।"

Q **आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत के बाद यह पहला बजट है, यह बजट किस तरह से देश को आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जाएगा?**

A आत्मनिर्भरता एक नया विचार नहीं है। प्राचीन काल जब भारत विश्व व्यापार का प्रमुख केंद्र था, हम अपनी जरूरतों के हिसाब से आत्मनिर्भर थे। 'आत्मनिर्भर भारत' दरअसल, 130 करोड़ भारतीयों की अभिव्यक्ति है, जिनको अपनी क्षमताओं और कौशल में पूरा भरोसा है। मई 2020 में लॉकडाउन के समय जब जरूरत थी, सरकार ने आत्म निर्भर भारत पैकेज (एएनबीपी 1.0) की घोषणा की। इसके बाद आगे भी रिकवरी बरकरार रखने के लिए, हम दो और आत्मनिर्भर भारत पैकेज (एएनबीपी 2.0 और एएनबीपी 3.0) लेकर आए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने हमारे समाज के सबसे अधिक संवेदनशील वर्गों– निर्धनों में निर्धनतम, दलितों, जनजातियों, वृद्धजनों, प्रवासी कामगारों और बच्चों को सहारा देने के लिए अपने संसाधनों में से

"कोरोना वैक्सीन के लिए दिए गए 35000 करोड़ रुपये इसी साल के लिए हैं। अगर इस से भी ज्यादा रुपयों की जरूरत होगी, तो मैं वो भी देने के लिए प्रतिबद्ध हूं। - निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री

Q&A

बजट तैयार करते वक्त प्राथमिकताएं क्या थीं?

इस बजट में हम सरकारी खर्च को बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा रोड बनेगा, अच्छा बंदरगाह बनेगा या जनता को अच्छी सुविधा मिलेगी, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा। जिसे कोर इंड्रस्टी कहते हैं, जैसे सीमेंट, स्टील, केबल, बिजली तार, वायरिंग, बिजली उत्पादन यूनिट.. इनमें मांग बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तब इसमें रोजगार बढ़ेगा और जब रोजगार बढ़ेगा तब जनता के हाथ में पैसा तुरंत आएगा। संपूर्ण विकास और अर्थव्यवस्था को रफ्तार तेज रफ्तार मिले इसीलिए हमने इसमें 6 स्तंभ तय किए।

मुश्किल से रास्ता निकाला। पीएमजीकेवाई, तीन एएनबीपी पैकेज और बाद में की गई घोषणाएं अपने आप में पांच मिनी बजट के समान थीं। आत्मनिर्भर पैकेजों ने ढांचागत सुधारों की हमारी गति को बढ़ाया।

Q **गांव-गरीब-किसान सरकार की प्राथमिकताओं में रहा है, ऐसे में बजट में उनके लिए क्या खास है?**

A सरकार किसानों को कल्याण के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस साल के शुरू में ही प्रधानमंत्री ने स्वामित्व स्कीम शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत गांवों में संपत्तियों के मालिकों को अधिकार के दस्तावेज दिए जा रहे हैं अब तक 1,241 गावों के लगभग 1.80 लाख संपत्ति मालिकों को कार्ड दिए गए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में हम इसे पूरे देश में लागू करने जा रहे हैं। हमने वित्तीय वर्ष 2022 में कृषि ऋण के लक्ष्य को भी बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये तक कर दिया है। हमारा फोकस पशुपालन, डेयरी और मछली पालन के क्षेत्र में और अधिक ऋण उपलब्ध कराने पर है। गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए पिछली बार के 30 हजार करोड़ की तुलना में इस बार 40 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नाबार्ड के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपये से एक माइक्रो इरिगेशन फंड स्थापित किया गया है। इसके लिए अब 5000 करोड़ रुपये और दिए गए हैं। कृषि और संबद्ध उत्पादों के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने और उसके निर्यात को बढ़ाने के लिए 'ऑपरेशन ग्रीन स्कीम' जो कि इस समय केवल टमाटर, प्याज और आलू पर लागू है, उसके दायरे को बढ़ाया गया है। अब इसमें जल्दी खराब होने वाले 22 और उत्पादों को शामिल किया जाएगा। ई-एनएएम से कृषि बाजार में जो पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा देखने में आई है उसको ध्यान में रखते हुए 1000 और मंडियों को ई-एनएएम के अंतर्गत लाया जाएगा। एपीएमसी को कृषि इंफ्रा फंड की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे यहां बुनियादी सुविधाएं और बेहतर हो सकें। गैर-संगठित क्षेत्र के श्रमिकों, विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों के लिए किए जा रहे हमारे प्रयास को और आगे बढ़ाने के लिए हम एक पोर्टल शुरू करेंगे जिस पर गिग कार्यकर्ता, बिल्डिंग और कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स तथा अन्य श्रमिकों के बारे में संबंधित सूचना संग्रहित की जा सके।

Q **प्रधानमंत्री हमेशा युवा ऊर्जा की बात करते हैं और आत्मनिर्भर भारत अभियान में उनकी भूमिका अहम बताते हैं। ऐसे में युवाओं को लेकर बजट कितना महत्वपूर्ण है?**

A 2016 में हमने एक राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। सरकार का प्रस्ताव प्रशिक्षुता अधिनियम में संशोधन करने का है, जिससे हमारे युवाओं को एप्रेंटिसशिप

यह सरकार लंबी अवधि की नीति बनाती है। सरकार सुधार के रास्ते पर चलेगी, आगे बढ़ती रहेगी। इस बात का ध्यान रखना होगा।

के और अवसर मिल सके। हम शिक्षा के बाद एप्रेंटिसशिप, इंजीनियरिंग में स्नातक और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए नेशनल एप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की वर्तमान योजना को फिर से संगठित करना चाहते हैं। UAE के साथ भागीदारी से एक प्रयास किया जा रहा है। भारत और जापान के बीच हमारा एक सहभागी इंटर ट्रेनिंग कार्यक्रम भी चल रहा है। हम अन्य देशों के साथ भी इसी तरह के प्रयास करने वाले हैं।

बजट 2019-20 में, मैंने भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग गठित करने के बारे में उल्लेख किया था। इसे लागू करने के लिए इस साल नियम बनाएंगे। यह एक स्वतंत्र निकाय होगा जिसमें निर्धारण, प्रत्यायन, विनियमन, और फंडिग के लिए चार अलग-अलग घटक होंगे।

Q **नीतिगत सुधार के जरिए 'ईज ऑफ लीविंग' सरकार का मंत्र है, किस तरह के सुधार इस बजट में किए गए हैं और इसका क्या असर पड़ेगा?**

A जल जीवन मिशन (शहरी) लांच किया जाएगा। इसका उद्देश्य सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन लगाने के साथ सभी को पानी उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही, 500 अमृत शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाएगी। इसे 2,87,000 करोड़ रूपए के खर्च से 5 वर्ष में लागू किया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021-2026 से 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रूपए के कुल वित्तीय आवंटन से लागू किया जाएगा।

वायु प्रदुषण की विकराल होती समस्या का समाधान करने के लिए, इस बजट में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई गई है। हम अगले 3 वर्षों में 100 और अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ देंगे तथा जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में एक गैस पाइप लाइन परियोजना शुरू की जाएगी। सड़क परिवहन, रेलवे और मेट्रो को लेकर भी कई बड़ी योजनाओं की घोषणा इस बजट में की गई है।

Q&A

आप देश की पहली पूर्णकालिक रक्षा और अब महिला वित्त मंत्री हैं, महिलाओं के लिए क्या सौगात है इस आम बजट में, जिन्हें पीएम अपने न्यू इंडिया के विजन के लिए केंद्र बिंदु मानते हैं?

उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसे 1 करोड़ नए कनेक्शन के साथ विस्तार दिया जा रहा है। इसके अलावा महिलाओं को सभी श्रेणियों और पर्याप्त सुरक्षा के साथ नाइट शिफ्ट में भी काम करने की अनुमति होगी। इस बार बजट में असम और पश्चिम बंगाल में चाय श्रमिकों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए के साथ शुरू की जा रही खास स्कीम विशेष रूप से महिलाओं और उनके बच्चों पर फोकस करेगी। स्टैंड अप इंडिया स्कीम में 'मार्जिन मनी' की आवश्यकता को 25% से 15% कम किया गया है।

Q **स्वास्थ्य क्षेत्र कभी भी राजनीति में अहम मुद्दा नहीं होता था, लेकिन पहली बार सरकार ने इस दिशा में अहम कदम उठाया है। भारत स्वस्थ्य हो, इस दिशा में बजट किस तरह प्रभावी होगा?**

A हां,जरूर। जनता को स्वास्थ्य की सुविधा देने के लिए गांव के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर जो भी संस्थान हैं, उन सभी को पैसा मिलेगा। वित्त आयोग ने भी यही सिफारिश की है। वे भी सुझाव दे रहे हैं कि पंचायत, स्थानीय निकायों, कचरा प्रबंधन, जल शोधन के लिए पैसा मिले। इसलिए जब हम स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की बात करते हैं तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि

जब हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करते हैं तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि स्वच्छता और पोषण भी इसमें शामिल हो। समग्र रूप से सुधार होगा तभी हम तय लक्ष्य हासिल करे सकेंगे।

सभी श्रेणी के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था लागू होगी और उनको कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत लाया जाएगा। महिलाओं को सभी श्रेणी में काम करने की अनुमति होगी।

- निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री

इसका रूप समग्र हो। यानी, सफाई और पोषण को अलग करके सिर्फ अस्पताल बनाना मतलब नहीं है। इसलिए हमने पोषण को भी इसमें जोड़ा है। प्रखंड स्तर पर क्रिटिकल केयर अस्पताल हमारे पास नहीं है, वो बनाना है। फिर आपको याद होगा कि लॉकडाउन शुरू होने के समय में हमारे यहां, कोविड जांच के लिए केवल दो लैब थीं। देशभर के सैंपल वहां भेजे जाते थे, फिर टेस्ट होकर वहां से आते थे। इस दौरान महामारी के समय हमने 2000 के करीब टेस्टिंग लैब तैयार की हैं। सभी राज्य के हरेक ब्लॉक में जांच करने के लिए लैब होना चाहिए। इसके साथ ही अब केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ्य भारत के नाम से एक नई योजना की शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत अगले 6 वर्षों में लगभग 64,180 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणाली और मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूती मिलेगी। साथ ही, नई बीमारियों का पता लगाने और इलाज के लिए संस्थानों का विकास होगा।

Q **एमएसएमई सेक्टर कोरोना काल में बुरी तरह प्रभावित हुआ था, जिसे पैकेज से मदद दी गई, इस सेक्टर के लिए बजट में क्या खास योजना बनाई गई है?**

A हमने लघु, कुटीर, एवं मध्यम उपक्रम (MSME) क्षेत्र को समर्थन देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस बजट में, मैंने इस क्षेत्र को इस वर्ष के बजट अनुमान के दोगुना से अधिक 15,700 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। कंपनी मामलों के तेजी से समाधान के लिए MSMEs के लिए विशेष ढांचा तैयार किया जाएगा। साथ ही MSME के लिए कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी बदली गई है।

Q **नोटबंदी के बाद जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था तेजी से डिजिटल और कैशलेस हो रही है, उसको भविष्य के आर्थिक भारत की नींव भी कह सकते हैं। कोरोना काल में डिजिटल लेनदेन ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए, ऐसे साहसिक निर्णय के पीछे सरकार का क्या रोडमैप है ताकि इसे और बढ़ावा मिले?**

A डिजिटल लेन-देन को और बढ़ावा देने के लिए इस बजट में एक प्रस्तावित योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये रखे गए हैं। यह योजना भुगतान के डिजिटल तरीके को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। ●

चौथी औद्योगिक क्रांति से मानवता की भलाई के लिए तैयार भारत

डिजिटलीकरण ही चौथी औद्योगिक क्रांति का आधार है, जिसके लिए बीते छह साल में भारत ने मजबूत ढांचा खड़ा किया और अपनी इसी मजबूती के सहारे दुनिया में भारत अनुकूल वातावरण प्रदान कर रहा है। विश्व आर्थिक मंच के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने इसे आर्थिक आत्मनिर्भरता आधार बताया...

आज जब भारत, न्यू इंडिया के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, अपने सामर्थ्य और संसाधनों को मजबूत कर रहा है, तो उसे चौथी औद्योगिक क्रांति का साथ मिलना, सोने पर सुहागे की तरह हो गया है। लेकिन बिना नींव के कोई भी इमारत खड़ी नहीं हो सकती, उसी तरह चौथी औद्योगिक क्रांति की सफलता भी इसी पर टिकी है कि किस देश में इसके लिए आवश्यक नींव तैयार है। बीते छह साल में केंद्र सरकार ने चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए भारत को तैयार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इसी का नतीजा है कि भारत अब दुनिया के निवेशकों के लिए व्यापार की नजी में पसंदीदा केंद्र बन रहा है। विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र करते हुए कहा कि भारत व्यापार करने के लिए एक "प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट" प्रदान करता है और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता वैश्वीकरण को मजबूत करेगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि चौथी औद्योगिक क्रांति में चार फैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पहला- कनेक्टिविटी, दूसरा- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तीसरा- स्वचालन और चौथ- वास्तविक डेटा। भारत इस समय दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां सबसे सस्ता डेटा उपलब्ध है, जहां दूर-दराज के क्षेत्रों में भी मोबाइल नेटवर्क होने के साथ लोगों के हाथों में स्मार्टफोन है। इसके अलावा दुनिया की ज्यादातर कंपनियों के इंजीनियरिंग सेंटर भी भारत में हैं। आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस के साथ मशीन लर्निंग में भी भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्षों से अपनी क्षमताओं के माध्यम से दुनिया को अवगत करा रहे हैं।

> **दुनिया के 400 शीर्ष कंपनियों के प्रतिनिधियों के सामने पीएम ने रखा नए भारत का संकल्प**

विश्व आर्थिक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने नामचीन कंपनियों के सीईओ के सवालों के दिए जवाब...

आत्मनिर्भरता के स्वरूप पर सीमेंस के अध्यक्ष और सीईओ जो कीसर के सवाल पर।

भारत ने 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान इसी संकल्प के साथ शुरू किया है कि हमारी अर्थव्यवस्था की क्षमता और लचीलेपन को बढ़ाया जाए। इस दशक में अर्थव्यवस्था को उच्च विकास पथ देने के लिए भारत ने एक के बाद एक कई सुधार किए हैं। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का मुख्य हिस्सा है- देश को मैन्युफेक्चरिंग और निर्यात हब बनाना। भारत में मैन्युफेक्चरिंग को बढ़ाने के लिए सरकार ने लगातार कई बड़े कदम उठाए हैं, सुधार किए हैं: **कॉरपोरेट टैक्स घटाया, जीएसटी दर कम की। टैक्स संरचना को आसान बनाया गया है। श्रम कानूनों में सुधार कर उद्योग को लचीले विकल्प दिए।**

इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कंपनी कानून में कई बिन्दुओं को डीक्रिमनलाइज किया गया है। प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए पीएलआई स्कीम को बढ़ावा दिया गया है। मैं आपको और आपके सभी साथियों को 26 बिलियन डॉलर की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं में सहभागी बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।

प्रधानमंत्री बोले- भारत संभावनाओं से भरा वैश्विक खिलाड़ी है। साथ-साथ आत्मविश्वास और नई ऊर्जा से भरा हुआ है।

इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं पर एबीबी के सीईओ ब्योर्न रोसेनग्रेन के सवाल पर।

इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए स्तंभ की तरह होता है। इसीलिए आज देश

वर्ष 2018 में भी दावोस के मंच से ही प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र किया था। कोरोना काल में यह सही साबित हुआ।

के लिए बुनियादी ढांचा पहली प्राथमिकताओं में से एक है। बीते 6 सालों में भारत में 57 हजार किलोमीटर अंतरराज्यीय राजमार्ग बनाए गए हैं। 58% से ज्यादा रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हुआ है। देश ने अपने पावर सेक्टर में 36 गीगावाट सौर क्षमता भी जोड़ी है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाएं अगले पांच सालों में लागू की जाएंगी। इसी तरह, देश के सभी आर्थिक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी मास्टर-प्लान भी बनाया जा रहा है। भारत प्रयासों की वजह से ही कोरोना महामारी के बावजूद 2020 में भारत में एफडीआई 13% बढ़ा है।

वित्तीय समावेशन पर मास्टरकार्ड के मुख्य कार्यकारी निदेशक अजय एस. बंगा के सवाल पर।

डिजिटलीकरण आज देश की प्राथमिकता भी है। डिजिटल रूप से सक्षम वित्तीय समावेशन के जरिए ही करोड़ों नागरिकों के बैंक खातों में पैसे पहुंचना और बिना बैंक से कैश निकाले उसका इस्तेमाल करना संभव हुआ। हमारी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऋण गारंटी योजना के द्वारा 1.3 मिलियन स्ट्रीट वेंडर्स, औपचारिक सिस्टम और डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ गए हैं। एमएसएमई की परिभाषा को बदलने का हमारा निर्णय, एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करेगा। एमएसएमई की सहायता के लिए, उन्हें नए अवसर देने के लिए हम कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका उदाहरण गर्वमेंट ई मार्केट प्लेस- जेम है। इसकी मदद से 450 हजार से ज्यादा एमएसएमई गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में ऑनलाइन हिस्सा ले रहे हैं।

डिजिटल जरूरतों को लेकर आईबीएम के अरविंद कृष्ण के सवाल पर।

अरविंद जी, जब मेरी पिछली बार आपसे बात हुई थी तो कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में हड़कंप था, अनेक देशों में लॉकडाउन था। तब उस दौर में भारत की डिजिटल होती इकोनॉमी ने देशवासियों की बहुत मदद की है। आज हमारे देश में 1.3 बिलियन आधार, 1.1 बिलियन मोबाइल कनेक्शन और 750 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ता हैं। हमारी सरकार का नजरिया साफ है- हमें पहुंच, समावेश और सशक्तीकरण के जरिए देश को ट्रांसफॉर्म करना है, और साथ ही उपभोक्ता की निजता भी सुनिश्चित करनी है। इसके लिए देश कई पहलुओं पर फोकस कर रहा है। पहला, डिजिटल दुनिया में सभी को पहुंच। आज देश में 3 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेन्टर चल रहे हैं। दूसरा, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। हमारा तीसरा पहलू है – सीमावर्ती प्रौद्योगिकियों की रिसर्च पर निवेश। इसी तरह

'आत्मनिर्भर भारत' वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेगा सरकार का लक्ष्य है समावेशन और सशक्तीकरण के जरिए बदलाव

चौथा पहलू है डाटा और निजता। डाटा सुरक्षा पर मजबूत कानून के लिए काम चल रहा है। ●

प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें

वैक्सीन मैत्री

अब दुनिया के लिए 'मेड इन इंडिया' वैक्सीन

घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित करते हुए कोरोना महामारी के खिलाफ मानवता को प्रमुखता देते हुए भारत अब पड़ोसी और भागीदार देशों को भी 'मेड इन इंडिया' वैक्सीन की आपूर्ति कर वसुधैव कुटुंबकम का दे रहा संदेश तो दुनिया के देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी वैक्सीन मैत्री के लिए भारत का जता रहे आभार

सर्वे सन्तु निरामयाः अर्थात् पूरा संसार स्वस्थ रहे, भारत की इस हजारों वर्ष पुरानी प्रार्थना पर चलते हुए संकट के इस समय में भारत ने अपनी वैश्विक जिम्मेदारी को भी शुरू से निभाया है। भारत ने बड़ी आबादी वाले इस देश में कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करके पूरी मानवता को बड़ी त्रासदी से बचाया है। अब जबकि भारत ने स्वदेशी वैक्सीन बनाकर दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है और दुनिया की भी उम्मीद पूरी करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इसकी शुरुआत हुई है- वैक्सीन मैत्री से।

पड़ोसी प्रथम नीति के साथ भारतीय टीके की आपूर्ति

पड़ोसी और प्रमुख साझेदार देशों से भारत में निर्मित टीकों की मांग पर विचार करते हुए भारत सरकार ने 20 जनवरी से भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, ओमान और सेशेल्स को वैक्सीन की आपूर्ति शुरू कर दी है। जबकि श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरीशस के संबंध में औपचारिक मंजूरी की प्रतीक्षा है।

> "भारत की सफलता को किसी एक देश की सफलता से आंकना उचित नहीं होगा। आज भारत ही है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान भी शुरू किया है। आज भारत, कोविड की वैक्सीन दुनिया के अनेक देशों में भेजकर, वहां पर टीकाकरण से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करके, दूसरे देशों के नागरिकों का भी जीवन बचा रहा है।
> –नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

दुनिया के लिए संजीवनी बन रहा भारत

भारत द्वारा कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने पर ब्राजील के राष्ट्रपति जायेर बोल्सनारो ने भारत को हनुमान बताया है। उन्होंने भगवान हनुमान की संजीवनी बूटी लेकर जाते हुए तस्वीर ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का आभार जताया है। उन्होंने हिंदी में भी 'धन्यवाद' लिखकर भारत के प्रति अपना समर्थन जताया है।

वैक्सीन से पहले कोरोना महामारी के दौरान भी भारत ने 150 से ज्यादा देशों को हाइड्रक्सीक्लोरोक्वीन, रेमडेसिविर और पैरासिटामोल जैसी दवाईयों के अलावा जांच किट, वेंटिलेटर, मास्क और अन्य चिकित्सा सहायता पहुंचाई थी। ब्राजील के राष्ट्रपति ने इसके लिए भारत को संजीवनी लाने वाले हनुमान की संज्ञा दी थी। टीकाकरण अभियान शुरू होने पर पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों और राजनेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए शुभकामनाएं भी दी। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने वैक्सीन की सफल शुरुआत और मित्र पड़ोसी देशों के प्रति उदारता के लिए बधाई दी। जबकि श्रीलंका के ही प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलीह और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने भारत की इस सफलता को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के अंत की शुरुआत बताया।

भारत ने पड़ोसी देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन की आपूर्ति शुरू कर फिर से अपनी वैश्विक प्रतिबद्धता दिखाई है तो जवाब में भूटान के विदेश मंत्री तंदी दोरजी ने कोविशील्ड टीकों की डेढ़ लाख खुराक के उपहार के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने कहा कि कोविशील्ड टीके की एक लाख खुराक मिलने से उनका देश बेहद खुश है। रिपोर्ट के मुताबिक,22 जनवरी तक भारत ने विभिन्न देशों को कोविशील्ड की 1.417 करोड़ खुराक पहुंचाई है। इसमें भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यामांर और सेशेल्स शामिल हैं। इनके अलावा भारत ने ब्राजील और मोरक्को सहित दुनिया के कई देशों को वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। यही नहीं, भारत में भी इस समय दुनिया का सबसे बड़ा टीकारकरण अभियान चल रहा है। 20 लाख लोगों को 11 दिन के भीतर वैक्सीन लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया है।

कोरोना वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त फ्रंटलाइन वर्कर और डॉक्टर

भारत में बने वैक्सीन की मांग अब दुनिया के अन्य देशों में होने लगी है, ऐसे में इस स्वदेशी वैक्सीन की विश्वसनीयता और बढ़ गई है। इतना ही नहीं, अब तक जितने फ्रंटलाइन वर्करों और डॉक्टरों ने टीका लगवाया है, उनका निजी अनुभव भी बताता है कि अब कोरोना के खिलाफ भारत की जंग अपने निर्णायक दौर में पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर मेडिकल कॉलेज की सफाई कर्मचारी तुसला तांडी कोरोना का पहला टीका लगवाने के बाद पूरी तरह स्वस्थ हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश के सागर जिले के सफाईकर्मी राजू बाल्मिकी कहते हैं कि टीका लगवाने के बाद उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई और वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला महिला अस्पताल की सफाईकर्मी केशा देवी भी कहती हैं, "मैंने पहला टीका लगवाया है और पूरी तरह स्वस्थ हूं। आप लोग भी टीका लगवाइए।"

भारत 18 दिनों में 40 लाख कोविड-19 टीकाकरण करने वाला दुनिया का सबसे तेज देश

17 देशों को अभी तक कोरोना वैक्सीन की 64 लाख डोज भेजी जा चुकी हैं।

60 और देशों ने भारत से मांगी कोरोना वैक्सीन

**आकंड़े 31 जनवरी तक*

भारत में टीकाकरण

41,38,918
लोगों को टीका लगाया गया 18 दिन में

कुल मरीज	एक्टिव केस	रिकवरी दर
1,07,77,284	1,60,057	97.08%

संक्रमण दर	मृत्यु दर
1.49%	1.43%

आकंड़े 2 फरवरी तक (स्रोतः स्वास्थ्य मंत्रालय)

भारत को जोड़ने वाले सरदार पटेल की प्रेरणा स्थली से जुड़ा देश

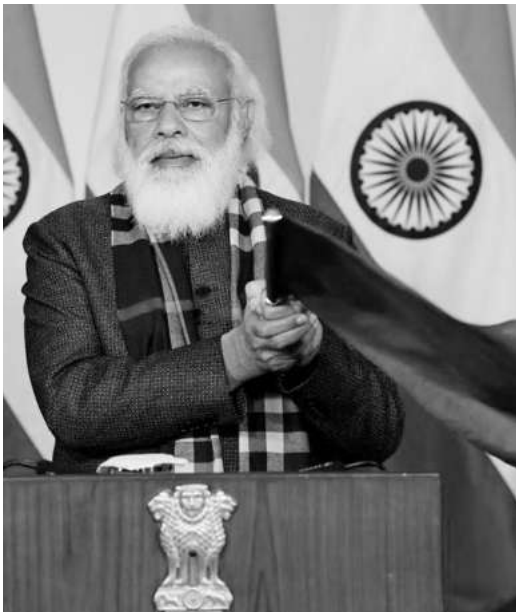

पटरी पर दौड़ती रेल गांवों को शहर से और लोगों की उम्मीदों को उनकी मंजिल से जोड़ती है। प्रधानमंत्री के विजन से अब भारतीय रेल 8 नई ट्रेनों के साथ सरदार पटेल की धरा केवड़िया से जोड़ेगी। देश-दुनिया के लाखों लोगों के आकर्षण का केंद्र बन चुकी विश्व की सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा- स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अपनी अद्भूत बनावट और आधुनिक सुविधाओं के कारण बन गई है देश-दुनिया का सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल

एक भारत, श्रेष्ठ भारत के प्रणेता सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात के केवड़िया स्थित प्रेरणा स्थली- 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' का पूरा क्षेत्र अब देश की राजधानी दिल्ली, धार्मिक नगरी वाराणसी, दक्षिण में चेन्नई, आर्थिक केंद्र मुंबई सहित देश के प्रमुख स्थानों से जुड़ गया है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही स्थान के लिए विभिन्न हिस्सों से आठ ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दिखाई गई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए रेल कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसके साथ ही केवड़िया रेलवे स्टेशन भारत का पहला ऐसा स्टेशन बन गया है जिसको शुरुआत से ही ग्रीन बिल्डिंग के रूप में विकसित किया गया है।

केवड़िया में खुलेंगे विकास के नए द्वार

दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा- स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का आकर्षण इस तरह बढ़ा है कि अब तक इसे अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा पर्यटक देख चुके हैं। पर्यटकों की लगातार बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए ही यहां तक देश के विभिन्न हिस्सों से सीधी रेल कनेक्टिविटी की सुविधा शुरू की गई है। इससे यहां तक की यात्रा सुगम, सुविधापूर्ण और किफायती होगी। इस कनेक्टिविटी के लिए

आठ जोड़ी ट्रेनें एक साथ एक जगह के लिए भारत में पहली बार

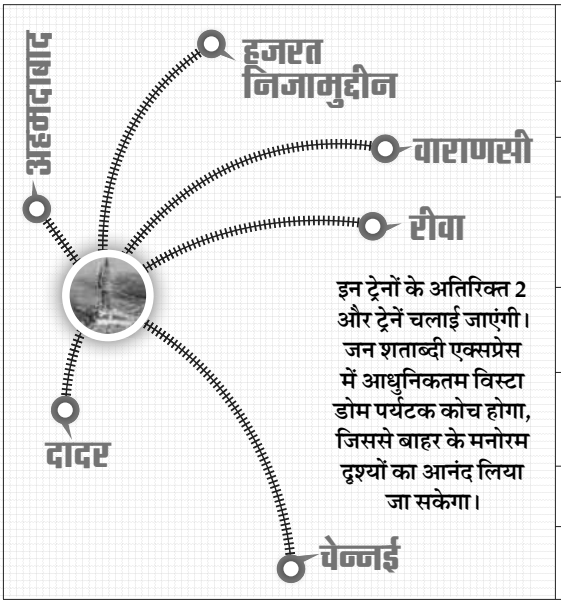

वाराणसी जं.- केवड़िया एक्सप्रेस	महामना एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
दादर-केवड़िया एक्सप्रेस	दादर-केवड़िया एक्सप्रेस प्रतिदिन
अहमदाबाद- केवड़िया एक्सप्रेस	जन शताब्दी एक्सप्रेस (प्रतिदिन)
हजरत निजामुद्दीन- केवड़िया एक्सप्रेस	निजामुद्दीन-केवड़िया संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार)
रीवा- केवड़िया	रीवा- केवड़िया एक्सप्रेस साप्ताहिक
चेन्नई- केवड़िया	चेन्नई- केवड़िया एक्सप्रेस साप्ताहिक
प्रताप नगर- केवड़िया मेमू	प्रतिदिन
केवड़िया-प्रताप नगर मेमू	प्रतिदिन

रेल कनेक्टिविटी से बदलेगी क्षेत्र की तस्वीर

- स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 5 किमी दूर न्यू केवड़िया रेलवे स्टेशन का निर्माण।
- डभोई, चांदोद और केवडिया के रेलवे स्टेशन लोकल थीम पर आधारित हैं। साथ ही 80 किमी के रेलखंड को विद्युतीकृत किया गया है।
- प्रतापनगर-डभोई खंड में ट्रेन की गति को बढ़ाकर 110 किमी प्रति घंटा किया गया है। इसे 130 किमी प्रति घंटा करने की योजना है।
- पवित्र नदी नर्मदा के तट पर बसे महत्वपूर्ण धार्मिक और प्राचीन तीर्थ स्थलों से कनेक्टिविटी।
- रोजगार और व्यापार के नए अवसर बनेंगे।

पीएम के संबोधन के अहम बिंदुः

- बढ़ते हुए पर्यटन के कारण यहां के आदिवासी युवाओं को रोजगार मिल रहा है, यहां के लोगों के जीवन में तेजी से आधुनिक सुविधाएं पहुंच रही हैं। इनोवेशन और अनुसंधान से भारतीय रेल के वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए 20 राज्यों के मेधावी युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर आज यहां दिख रही है। आज का ये आयोजन भारतीय रेल के विजन और सरदार पटेल के मिशन, दोनों को परिभाषित कर रहा है। आज केवड़िया सुदूर इलाके में बसा एक छोटा सा ब्लॉक नहीं रह गया है, बल्कि सबसे बड़े पर्यटक स्थल के रूप में आज उभर रहा है।

प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें

पहली ग्रीन बिल्डिंग केवड़िया स्टेशन की विशेषताएं

- इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा भारत के पहले रेलवे स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग का प्रमाण मिला।पहले दो लेवल में वातानुकूलित वेटिंग रूम और वीवीआईपी लाउंज जैसी यात्री सुविधाएं।
- तीसरे लेवल पर आदिवासी आर्ट गैलरी, दर्शक दीर्घा से पर्यटक को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने की सुविधा।
- सर्कुलेटिंग क्षेत्र के प्रमुख स्थान पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की 12 फीट ऊंची प्रतिकृति स्थापित की गई है

भारतीय रेल ने चांदोद से केवड़िया तक 32 किमी की नई ब्रॉडगेज रेल लाइन बिछाई है, साथ ही डभोई से चांदोद तक 18 किमी नैरो गेज लाइन को ब्रॉड गेज में बदला है। यह राह आसान नहीं थी। भारी वर्षा और अचानक कोरोना जैसी आपदा के बावजूद बुलंद हौसलों ने इसे रिकॉर्ड समय में पूरा करके विकास की नई कहानी लिखी है। रेल से जुड़ जाने से यहां के लोकल रोजगार और व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी मजबूती मिलेगी।●

नेताजी को नमन करने विशेष तौर से कोलकाता पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस के घर नेताजी भवन का भ्रमण किया।

सशक्त भारत और सोनार बांग्ला की प्रेरणा नेताजी

राष्ट्र के प्रति नेताजी की अदम्य भावना और निस्वार्थ सेवा की याद में केंद्र सरकार ने अब उनकी जयंती को पराक्रम दिवस घोषित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित समारोह में दिया संदेश-नेताजी ने जिस सशक्त भारत की कल्पना की थी, आज एलएसी से एलओसी तक भारत का यह अवतार देख रही है दुनिया

आजादी का बिगुल बजाने वाले देश के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती अब हर साल 'पराक्रम दिवस' के रूप में मनाई जाएगी। इसका मकसद देश के लोगों और खास तौर से युवाओं को प्रेरित करना, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य से काम करने के लिए प्रेरित करने के साथ नेताजी की तरह ही देशभक्ति की भावना का संचार किया करना है। केंद्र सरकार ने नेताजी की 125वीं जयंती वर्ष को राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाने का फैसला लिया है। 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष में साल भर चलने वाले समारोहों का उद्घाटन किया। इस मौके पर कोलकाता में 'निर्भीक सुभाष' नाम से एक स्थायी प्रदर्शनी और प्रोजेक्शन मैपिंग शो का उद्घाटन, नेताजी की थीम पर 'आमरा नूतन जोउबोनेरी दूत' का आयोजन और स्मारक सिक्का व डाक टिकट भी जारी किया गया। भारतीय रेलवे ने भी महानायक को नमन करते हुए पराक्रम दिवस के अवसर पर कोलकाता से कालका तक जाने वाली ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस रख दिया है। इसके साथ ही अब सरकार हर साल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार देगी।●

नेताजी की 125वीं जयंती को साल भर राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा।

- अब 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया। 2015-16 में नेताजी से जुड़ी सौ से ज्यादा फाइल सार्वजनिक की गई।
- अंडमान में नेताजी की ओर से तिरंगा फहराए जाने की 75वीं वर्षगांठ पर 2018 में तिरंगा फहराया गया और उस द्वीप का नाम नेताजी के नाम पर रखा गया। रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप को शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप नाम दिया गया।
- आजाद हिंद सरकार के गठन की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले में सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय स्थापित किया गया।

"

नेता सुभाष चंद्र बोस गरीबी, अशिक्षा, बीमारी को देश की सबसे बड़ी समस्याओं में गिनते थे। इन समस्याओं के समाधान के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा। जो भूमिका नेताजी ने देश की आजादी में निभाई थी, आज वही भूमिका पश्चिम बंगाल को आत्मनिर्भर भारत अभियान में निभानी है। -नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें

कोरोना के बाद की दुनिया के अनुकूल होगा कौशल विकास का तीसरा चरण

कोरोना ने जिंदगी जीने का तरीका बदला है, ऐसे में केंद्र सरकार ने नए परिवेश के मुताबिक युवाओं को नए अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की है। करीब 949 करोड़ रु. खर्च कर 8 लाख युवा होंगे तैयार

वर्षों तक संघर्ष के बाद जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा के समीर अहमद नजर आज एक पेशेवर हेयर स्टाइलिस्ट के तौर पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हैं। इसके लिए वे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का आभार जताते हैं। इसी तरह प्रीतम और उसके दोस्त की भी कहानी है, जो दिन-रात मेहनत करके भी अपनी कमाई से परिवार का भरण-पोषण ठीक से नहीं कर पाते थे। लेकिन कौशल विकास केंद्र से इंडस्ट्रियल वेल्डिंग का कोर्स करने के बाद उसे बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। प्रीतम का कहना है, "शिक्षा कम होने की वजह से महज 8 हजार रु. की आमदनी होती थी। लेकिन कौशल प्रशिक्षण के बाद बड़ी कंपनी में नौकरी लगी और अच्छी सैलरी मिलने लगी। इस क्षेत्र में और भी बड़े अवसर है क्योंकि इस तरह के प्रशिक्षित लोगों की मांग उड्डयन से लेकर हर उद्योग में है।"

हुनर के विकास से जिंदगी की मुश्किलें किस तरह से कम होती है, इसकी ये चंद मिसालें हैं जिसका जरिया बन रहा है स्किल इंडिया मिशन। आज यह मिशन युवाओं की जिंदगी को कौशल से संवार कर न सिर्फ आत्मनिर्भर बना रहा है बल्कि परिवार की दशा-दिशा बदलने में भी सहायक साबित हो रहा है। लेकिन अब जबकि कोरोना ने जिंदगी जीने का तरीका बदल दिया है तो इसके मुताबिक नए कौशल की भी जरूरत है। इसी दीर्घकालिक सोच के साथ केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की है। जिसका मकसद नए युग के लिहाज से युवाओं को लैस करना है।●

पीमकेवीआई-3, नए युग में नया कौशल

- पीएम कौशल विकास योजना का तीसरा चरण पूरे देश के 600 से अधिक जिलों में शुरू किया गया।
- 37 सेक्टर्स, 300 से अधिक पाठ्यक्रम का प्रस्ताव, जो 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू।
- 15 से 45 वर्ष के युवाओं की स्किलिंग, रिस्किलिंग और अपस्किलिंग। 729 कौशल केंद्र, स्किल इंडिया के तहत सूचीबद्ध अन्य कौशल केंद्र और 200 से अधिक आईटीआई द्वारा प्रशिक्षण।
- जिला कौशल समितियों की योजना बनाने, प्लेसमेंट और स्वरोजगार में अहम भूमिका। अभ्यर्थियों के लिए 2 लाख रुपये का 3 वर्षीय आकस्मिक बीमा या कौशल बीमा की व्यवस्था।

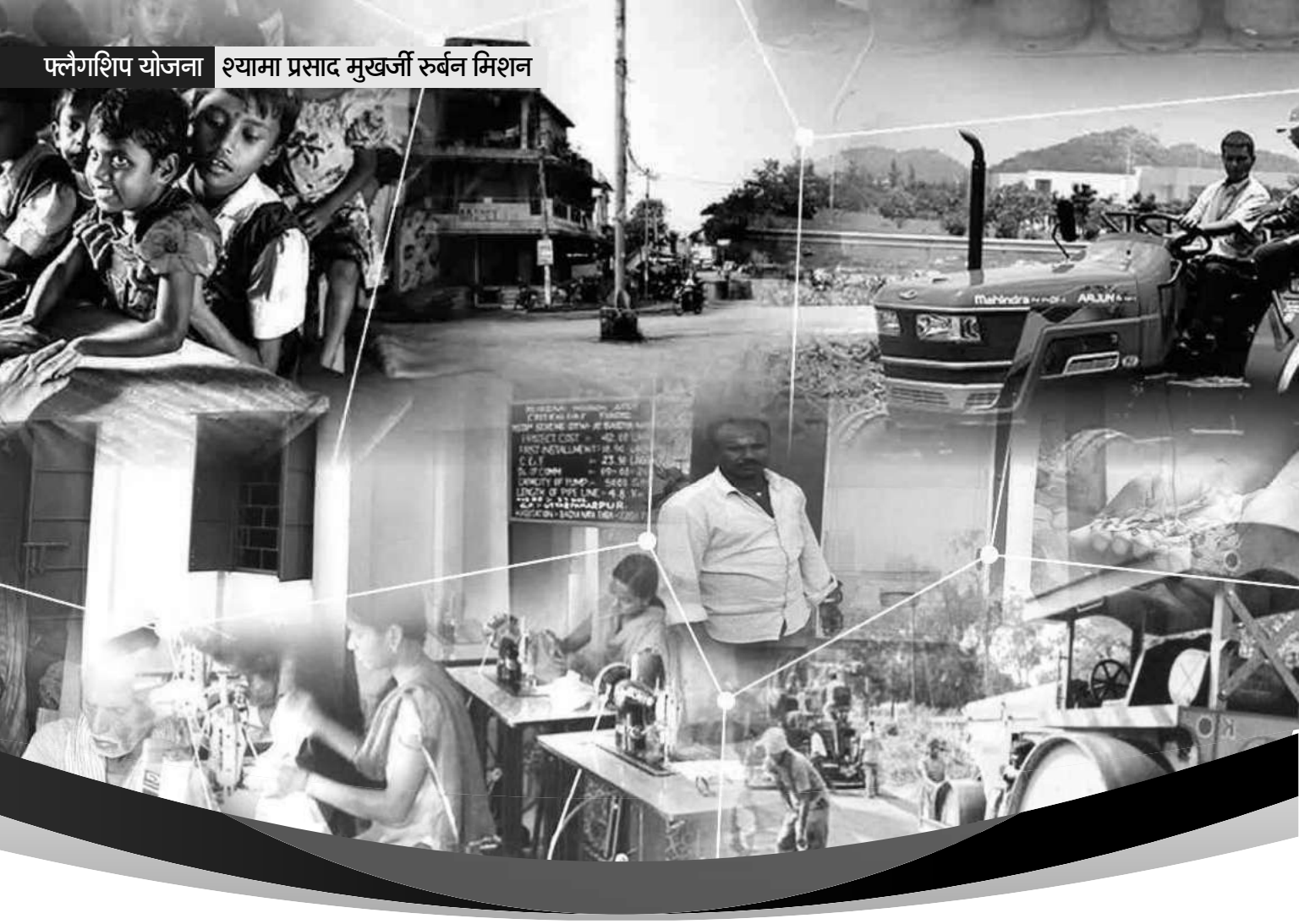

डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन

गांव की आत्मा, शहरों सा विकास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में आपने अक्सर 'ईज ऑफ लिविंग' का जिक्र सुना होगा। लेकिन, जीवन की सुविधाओं के विस्तार के लिए उपयोग किया जाना वाला 'ईज ऑफ लिविंग', शब्द सिर्फ शहरों के लिए नहीं है। यह उन गांवों के लिए भी है जिनमें भारत की 68.8 फीसदी आबादी बसती है। इसी आबादी को शहरों की तरह सुविधाएं देने के लिए केंद्र सरकार ने पहली बार वर्ष 2016 में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की शुरुआत की

ग्रामीण भारत में रहने वाला नागरिक भी चाहता है कि उसे रोजगार के साथ अच्छी शिक्षा, अच्छा अस्पताल, बिजली,पानी और इंटरनेट की सुविधा मिले। इसीलिए गांवों में रहने वाले शहरों की ओर चले जाते हैं। इसे देखकर आपके मन में भी यह ख्याल आया ही होगा कि क्यों आखिर लोगों को गांव में ही वो सुविधाएं नहीं मिलतीं, जिनकी तलाश में वो शहर आते हैं। शहरों में हर रोज बढ़ने वाली बस्तियां खत्म कर गांवों में अंतिम छोर तक विकास क्यों नहीं पहुंचता? इसी तस्वीर को बदलने की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ से की थी। प्रधानमंत्री

ऐसे आया रुर्बन मिशन का विचार

गांवों के विकास के लिये पूर्व राष्ट्रपति स्व. डॉ.अब्दुल कलाम ने 'पुरा' (providing urban amenities of rural areas) का विचार प्रस्तुत किया जिसके तहत 4 प्रकार की ग्रामीण-शहरी कनेक्टिविटी की बात की गई थी-फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक, नॉलेज तथा इकोनॉमिक कनेक्टिविटी। हालांकि, 'पुरा' के इस पायलट फेज के वांछित परिणाम नहीं मिल सके। इसके बाद रुर्बन मिशन की शुरुआत की गई।

1,842.97
करोड़ रु. जारी कर चुकी है केंद्र सरकार अभी तक

- रुर्बन का सीधा-सीधा अर्थ ऐसे गांव से है जिसका विकास ऐसा हो, जिसकी आत्मा गांव की हो और सुविधा शहर की। इसमें ध्यान रखा जाता है कि गांव का विकास शहर बनाने वाला हो।
- इसके तहत 21 फरवरी 2016 को योजना शुरू होने के शुरुआती 5 वर्षों में 300 क्लस्टर(समूह) विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। फरवरी 2020 तक 300 क्लस्टर आवंटित किए थे, जिनमें से 296 को मंजूरी मिल गई थी। रुर्बन क्लस्टर (समूहों)की 2 श्रेणियां हैं: गैर-आदिवासी और आदिवासी।
- ये क्लस्टर्स भौगोलिक रूप से नजदीक कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनाए गए। मिशन के तहत रुर्बन क्षेत्र में लगभग 15-20 गांवों का समूह आता है, जहां 30 से 40 लाख आबादी निवास करती है।
- इन क्लस्टर्स के चयन के लिये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाई, जिसके तहत जिला,उप-जिला एवं गांव के स्तर तक विभिन्न पहलुओं, जैसे- जनसंख्या, आर्थिक संभावनाओं, क्षमताओं, पर्यटन इत्यादि का विश्लेषण किया गया है।
- इसके अंतर्गत कौशल विकास, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण गोदामों का निर्माण, डिजिटल शिक्षा, स्वच्छता, घर-घर तक जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क, जल निकासी, मोबाइल स्वास्थ्य यूनिट, स्कूली एवं उच्च शिक्षा में सुधार, ई-ग्राम कनेक्टिविटी व एलपीजी गैस आपूर्ति सेवा इत्यादि शामिल की गईं हैं।
- नीति आयोग ने फरवरी 2020 में अगले 3 वर्षों में 1,000 से अधिक क्लस्टरों के लिए एक नया और विस्तारित कार्यक्रम प्रस्तावित किया है।

"इसका लाभ हिंदुस्तान के हर कोने को मिलने वाला है। और देखते ही देखते शहरों पर दबाव कम होगा। गांवों से बाहर जाने वालों के लिए एक अच्छी जगह उपलब्ध हो जाएगी, नए शहरों का निर्माण हो जाएगा। ये नए शहर व्यवस्थित होंगे, आयोजित होंगे, आर्थिक गतिविधि के साथ जुड़े हुए होंगे। -नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

मोदी के शब्दों में, "हम भारत में सिर्फ स्मार्ट सिटी बनाना नहीं चाहते, स्मार्ट विलेज भी बनाना चाहते हैं।"यानी भारत के गांव भी स्मार्ट हों और वहां वो सारी सुविधाएं मौजूद हों जिनकी तलाश में ग्रामीण, शहरों की ओर पलायन करते हैं। इसका नाम भारत को एक देश-एक विधान, एक प्रधान का नारा देने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन । यह नाम Rural-Urban दोनों को मिला कर रखा गया है। इसमें Rural(ग्रामीण) के शुरूआती तीन अक्षर Rur और Urban(शहरी) के अंतिम के तीन अक्षर banको मिला कर Rurban यानी रुर्बन रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को नयी गति प्रदान करने के साथ-साथ बुनियादी सेवाओं में बढ़ोतरी करना है।

गांवों का विकास होगा तो देश का भी विकास सही मायने में हो सकेगा। रुर्बन मिशन की संकल्पना का आधार यही विचार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं- "ये रुर्बन की जो कल्पना है, उसमें उसको ग्रोथ सेंटर बनाने की कल्पना है। आर्थिक विकास की गतिविधि का केंद्र बिंदु बनाने की कल्पना है। छोटे-छोटे बाजार होंगे, कारोबार अगल-बगल के 5-10 गांवों के लिए चलता होगा तो धीरे-धीरे वो रुर्बन बन जाएंगे।" ●

न्यू इंडिया में अब सम्मानित होने लगे गुमनाम नायक

वो कोई बहुत बड़ा नाम नहीं हैं। उनके इलाके से बाहर शायद उन्हें कोई जानता भी नहीं। लेकिन उनका काम बड़ा है और इस काम के पीछे है संघर्ष करने का उनका माद्दा। साथ ही सफलता के नए आयाम गढ़ने की उनकी जुझारू क्षमता की कहानी...जी हां, ये नए भारत के पद्म पुरस्कार विजेता हैं। जिनके संघर्ष पथ को जानकर अब पूरा देश उनसे प्रेरणा ले रहा है...

लोकतंत्र में आमजन की भागीदारी सिर्फ राजसत्ता तक सीमित नहीं होती। बल्कि यह संस्कृति, शिक्षा से लेकर हर एक क्षेत्र में भी होती है। इसलिए पद्म पुरस्कार जैसे देश के अहम सम्मान में भी यह भागीदारी होनी चाहिए। वर्ष 2014 से केंद्र सरकार ने इसकी शुरुआत की है। इसी का नतीजा है कि अब पद्म पुरस्कार देश में साधारण रहकर असाधारण काम करने वाले ऐसे गुमनाम नायकों को दिया जा रहा है, जिनके बारे में उनके क्षेत्र से बाहर लोगों ने शायद सुना भी न हो।

लाल बत्ती पर रोक लगाकर वीआईपी कल्चर को खत्म करने की दिशा में पहल करने वाली केंद्र सरकार की प्राथमिकता में सामान्य नागरिक सबसे ऊपर है। प्रधानमंत्री मोदी देश के विकास में हर व्यक्ति के योगदान को महत्वपूर्ण मानते हैं और इस बात पर जोर देते रहे हैं कि छोटा से छोटा प्रयास भी देश में बड़ा बदलाव

"हमें उन सभी पर गर्व है, जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत राष्ट्र और मानवता के लिए काम करने वाली हस्तियों के योगदान को सम्मानित करता रहा है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की इन असाधारण विभूतियों ने दूसरों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने का काम किया है। -नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

शिंजो आबे
पद्म विभूषण

एस पी बालासुब्रमण्यम
पद्म विभूषण

तरुण गोगोई
पद्म भूषण

शिंजो आबे, एसपी को पद्म विभूषण

पद्म विभूषण और पद्म भूषण के साथ पद्मश्री की पूरी सूची देखने के लिए दिए गए लिंक पर जाएं।

बिना थके-बिना रुके संघर्ष पथ पर चलकर बने प्रेरणा

पद्म पुरस्कारों की सूची में ऐसे कई नाम हैं, जिन्हें आप और हम भलिभांति जानते हैं। लेकिन इसके साथ ही इस सूची में ऐसे कई नाम भी हैं जो आमतौर पर बड़े-बड़े शहरों में, अख़बारों में, टी.वी. में, समारोह में नज़र नहीं आते हैं। लेकिन ये नाम, प्रशंसा की परवाह किए बगैर देश में बदलाव लाने के लिए जमीनी स्तर पर निस्वार्थ भाव से बिना थके कार्य करते रहे और अपना लक्ष्य हासिल करने में सफल रहे।

बीरूबाला रभा, असम

जिनकी कोशिशों से असम विधानमसभा को डायन हत्या निषेध कानून बनाना पड़ा

बीरूबाला रभा मात्र 6 साल की थीं जब उनके पिता का देहांत हो गया। 15 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। कपड़े बुनकर अपने 3 बच्चों का भरण-पोषण करने वाली बीरूबाला की जिंदगी में नया मोड़ 1980 में आया जब उनके बेटे को टायफाइड हो गया। जादू टोने वाले ने कहा-बेटा मर जाएगा। लेकिन किसी तरह जान बच गई। बीरूबाला ने देखा कि असम के कई इलाकों में इन्हीं जादू-टोने वालों के कहने पर महिलाओं को डायन बताकर हत्या कर दी जाती है। उन्होंने महिलाओं का समूह बनाकर इसके खिलाफ आवाज उठाई। अब तक 42 महिलाओं की जान बचा चुकीं बीरूबाला के प्रयासों की बदौलत विधानसभा ने 'डायन हत्या निषेध' विधेयक पारित किया।

पप्पम्माल, तमिलनाडु

105 साल की उम्र में ऑर्गेनिक खेती करने वाली दादी

60 साल की उम्र में जब हम अपने रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं, तमिलनाडु की रहने वाली पप्पम्माल 105 साल की उम्र में लोगों को ऑर्गेनिक खेती की प्रेरणा दे रही हैं। वे खुद अपने 2.5 एकड़ के खेत में ऑर्गेनिक खेती करती हैं। यही नहीं, पप्पम्माल के प्रयासों की बदौलत अब इस इलाके के कई किसानों ने जैविक खेती की ओर रुख किया है। खेती करने के साथ ही वो कृषि से जुड़े दूसरे कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए जानी जाती हैं। यही नहीं एम. पप्पम्माल तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय की सलाहकार समिति का भी हिस्सा हैं।

ला सकता है। 'न्यू इंडिया' के निर्माण में देश के हर नागरिक का योगदान सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कार की पूरी प्रक्रिया बदल दी। अब पद्म पुरस्कार के लिए व्यक्ति की पहचान नहीं बल्कि उसके काम का महत्व बढ़ गया है। न्यू इंडिया में देश का सामान्य व्यक्ति भी अपने उत्कृष्ट कार्य के जरिए देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार-पद्म पुरस्कार पा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र करते हुए अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में कहा था- "हर वर्ष

डॉ टी. वीराराघवन, तमिलनाडु

फीस में 2 रुपये लेने वाले डॉक्टर

चेन्नई जैसे किसी बड़े शहर में रहकर क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि आज के समय में कोई डॉक्टर मात्र 2 या 5 रुपये फीस लेकर आपका इलाज करेगा? लेकिन उत्तरी चेन्नई में डॉ. टी. वीराघवन इसी के लिए मशहूर हैं। वीराराघवन ने 1973 में मरीजों से मात्र 2 रु. फीस लेकर इलाज करना शुरू किया। बाद में उन्होंने इसे 5 रु. कर दिया। दूसरे डॉक्टरों ने उनका विरोध किया, कहा से कम 100 रुपया फीस करें। इसके विरोध में वीराराघवन ने फीस लेना ही बंद कर दिया।

नारायण देबनाथ, पं. बंगाल

सबसे लंबी कॉमिक स्ट्रिप का रिकॉर्ड

दुनिया में किसी एक आर्टिस्ट के सबसे लंबी कॉमिक स्ट्रिप चलाने का रेकॉर्ड किसके नाम है? इस सवाल के जवाब में शायद अच्छे-अच्छे गच्चा खा जाएं। मगर ये सम्मान हासिल है प. बंगाल के नारायण देबनाथ को। 97 साल के देबनाथ पिछले 70 से भी ज्यादा सालों से बंगाली कॉमिक स्ट्रिप बनाते आ रहे हैं। वह पहले और इकलौते भारतीय कॉमिक आर्टिस्ट हैं, जिन्हें डीलिट मिला है। उनकी कॉमिक्स का एक किरदार 'बन्तुल' बंगाल के घर घर में जाना पहचाना नाम है।

सुलट्रिम चोंजोर, लद्दाख=

संपत्ति बेचकर बनाई 38 किलोमीटर सड़क

कश्मीर और लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाके में रोड कनेक्टिविटी कोई आसान बात नहीं है। मौसम की मार और दुर्गम इलाके की अपनी चुनौतियां हैं। लेकिन कारगिल के जंस्कार क्षेत्र में 79 वर्षीय सुलट्रिम चोंजोर ने वहां लोगों के लिए अपनी संपत्ति बेचकर 57 लाख रुपये की मशीनरी खरीदी और 38 किलोमीटर लंबी सड़क बना डाली। इससे पहले हिमाचल और अन्य इलाकों की तरफ जाने के लिए स्थानीय लोगों को कई दिन पैदल चलने के बाद वाहनों में भारी भरकम राशि देनी पड़ती थी।

सुजीत चटोपाध्यादय , पं. बंगाल

सालभर में 2 रुपये फीस लेने वाले टीचर

आज के दौर में जब हम 2 रुपये में कुछ भी न आने की दुहाई देते हैं, पं. बंगाल के बर्धमान जिले में सुजीत चटोपध्याय अपनी पाठशाला में मात्र 2 रुपया साल की फीस पर देश का भविष्य गढ़ रहे हैं। 18 साल पहले रिटायर होने वाले चटोपाध्याय की कोचिंग में 300 बच्चे हैं। चटोपाध्याय कहते हैं, गरीब घर के बच्चे कोचिंग की महंगी फीस कैसे चुका सकते हैं। इसी ख्याल के साथ अपनी कोचिंग शुरू की थी। उम्मीद नहीं थी कि उनके काम को इतना सम्मान मिलेगा।

पद्म-पुरस्कार देने की परम्परा रही है लेकिन इसकी पूरी प्रक्रिया बदल गई है। अब कोई भी नागरिक किसी को भी नोमिनेट कर सकता है। ऑनलाइन हो जाने से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो गई है।" भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। वर्ष 2021 के लिए 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई है। जिन जानीमानी हस्तियों को यह सम्मान मिला है उनमें भारत

अंशु जेमसेन्पा, अरुणाचल प्रदेश

5 दिन में 2 बार फतेह किया एवरेस्ट

दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को जीतने का सपना हर पर्वतारोही देखता है। लेकिन दो बच्चों की मां 41 वर्षीय अंशु जेनसेन्पा ने वो कर दिखाया जो लोग सोच भी नहीं सकते। अंशु 5 दिन में 2 बार एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली अकेली महिला हैं। 16 मई 2017 और फिर 21 को। दूसरी चढ़ाई खत्म करने में उन्हें 118 घंटे और 30 मिनट लगे। अंशु अभी तक कुल 5 बार एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुकी हैं।

लाखा खान, राजस्थान

देश के इकलौते प्यालेदार सिंधी सारंगी वादक

जोधपुर की बाप तहसील के रनेरी गांव में लंगा समुदाय के पारंपरिक संगीतकारों के परिवार में जन्मे लाखा खान ने बचपन में ही गायन की शुरुआत कर दी थी। लाखा खान मांगणियार समुदाय में प्यालेदार सिंधी सारंगी बजाने वाले एकमात्र कलाकार हैं। हिन्दी, मारवाड़ी, सिंधी, पंजाबी और मुल्तानी सहित छह भाषाओं में गाने वाले लाखा खान को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित देश विदेश में कई बार पुरस्कृत किया जा चुका है। लाखा खान ने जटिल वाद्ययंत्र सिंधी सारंगी में महारत हासिल की।

आचार्य रामयत्न शुक्ल, उत्तर प्रदेश

89 साल की उम्र में संस्कृत की मुफ्त शिक्षा

किसी देश के संस्कारों की झलक वहां की संस्कृति में मिलती है, फिर भारत को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। जहां संस्कृत को देवभाषा माना जाता है। देश की नई पीढ़ी को इसी संस्कृत भाषा के करीब लाने की कमान थामे हुए हैं वाराणासी के 89 साल के आचार्य रामयत्न शुक्ल। आचार्य शुक्ल काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं। वे बनारस यूनिवर्सिटी के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में प्रफेसर के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

भूरी बाई, मध्य प्रदेश

हिंदी नहीं आती थी, पेंटिंग से बनी पहचान

गरीबी में अपना पूरा बचपन बिताने वाली भूरी बाई बरिया कभी हिंदी तक ठीक से नहीं बोल पाती थीं। लेकिन चित्रकला के उनके शौक ने 'पिथोरा पेंटिंग' को दुनियाभर में पहचान दिलाई। भूरी बाई पहली आदिवासी महिला हैं, जिन्होंने गांव में घर की दीवारों पर 'पिथोरा पेंटिंग' करने की हिम्मत की है। कभी भोपाल के 'भारत भवन' में मजदूरी करने वालीं भूरी बाई अब वहीं नजदीक के जनजातीय संग्रहालय में कलाकार के पद पर काम कर रही हैं।

के साथ अपनी दोस्ती को नए आयाम तक पहुंचाने वाले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण सम्मान देने की घोषणा की गई है। तमिलनाडु के रहने वाले महान दिवंगत गायक एसपी सुब्रमण्यन को भी पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण सम्मान दिया गया है। ●

सम्मान निधि के 2 साल और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के 6 साल

आत्मनिर्भर कृषि के लिए किसानों में अब जागा एक नया भरोसा

हर कदम पर किसानों के हितों का ध्यान रख रही केंद्र सरकार की योजनाएं दशकों से उपेक्षित और विकास से वंचित अन्नदाताओं को सशक्त बना रही हैं। दो साल पहले शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर वाली पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 1 लाख 13 हजार करोड़ से ज्यादा राशि हस्तांतरित की जा चुकी है तो किसानों की खेत और फसल की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से 6 साल पहले शुरू की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से बढ़ रही किसानों की उपज और आमदनी

फरवरी का दूसरा पखवाड़ा सिर्फ कैलेंडर में दर्ज महीना नहीं, बल्कि किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध केंद्र सरकार की ओर से देश के अन्नदाता को नया सहारा और उनके योगदान को सम्मान देने वाला भी है। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के महज 8-9 महीने बाद ही 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्रीगंगानगर से ऐसी योजना की शुरुआत की गई, जिससे न सिर्फ किसानों की फसल की उत्पादकता बढ़े, बल्कि उनकी आमदनी दोगुनी करने में भी मदद मिले। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने 24 फरवरी 2019 को भी एक ऐतिहासिक कदम उठाया और देश के छोटे-बड़े सभी किसानों के लिए सम्मान निधि की शुरुआत उत्तर प्रदेश की धरती से की। इसका मकसद हर चार महीने में 2 हजार रु. की किस्त सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंचाकर किसानों की बीज, खाद, कीटनाशक जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करना और महाजन के कर्ज में डूबने से बचाना

> **सम्मान निधि की राशि किसानों के खाते में सीधे जमा हो रही है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, सीधा-सीधा किसान के पास चला गया। इस योजना का जो लक्ष्य था वो हासिल हो रहा है। हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहुंचे और जरूरत के समय पहुंचे इस उद्देश्य में ये योजना सफल रही है।**
> **– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

सम्मान निधि किसान की मुस्कान

किसान सम्मान निधि योजना की पूरी जानकारी https://pmkisan.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर हासिल की जा सकती है। किसान इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। इस योजना के तहत अभी तक 11.52 करोड़ लाभार्थी पंजीकृत किए जा चुके हैं।

स्वस्थ धरा, खेत हरा

- वर्ष 2015 में अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया गया था और देश के हर खेत के सही पोषण के लिए केंद्र सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी।
- इस योजना में हर दो साल में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है ताकि मिट्टी की पोषण की कमी को दूर कर उपज और किसानों की आय बढ़ाई जा सके। ।
- पहले चरण में 2015-17 तक 10.74 करोड़ कार्ड और दूसरे चरण में 2017-19 तक 11.69 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।
- इस योजना में केंद्र सरकार 700 करोड़ रु. से अधिक खर्च कर चुकी है।
- देश में 429 से अधिक नई स्थायी मृदा जांच प्रयोगशालाएं, 102 नई पोर्टेबल जांच प्रयोगशालाएं और 9 हजार के करीब लघु प्रयोगशाला उपलब्ध है।
- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद(नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल) के अध्ययन के मुताबिक रसायनिक ऊर्वरकों के प्रयोग में 8-10 फीसदी की कमी आई है और उपज में 5-6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

कैसे ले सकते हैं लाभ

मृदा स्वास्थ्य कार्ड में 6 फसलों के लिए दो तरह के उर्वरकों की सिफारिश की गई है, इसमें जैविक खाद भी शामिल है। अतिरिक्त फसल के लिए भी किसान सुझाव मांग सकते हैं। एसएचसी पोर्टल https://soilhealth.dac.gov.in/ से किसान अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में सभी जानकारी उपलब्ध है।

था। एक तरफ मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ऊर्वरकों के उपयोग से मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों में होने वाली कमी दूर करने के उद्देश्य में सकारात्मक परिणाम दे रही है तो दूसरी तरफ सम्मान निधि योजना खास तौर से छोटे किसानों के लिए वरदान बन रही है। पिछले दो सालों में इस योजना के तहत अब तक 10.60 करोड़ भूधारी जोत किसानों के खाते में 1 लाख 13 हजार करोड़ रु. से अधिक की राशि जमा की जा चुकी है। हरियाणा के किसान सरदार सिंह, सुन्दर सिंह, गुजरात के किसान पटेल घनश्यामभाई धीरूभाई, मध्य प्रदेश के मूलचंद मेहवाड़ा या फिर तेलंगाना के एम. सुधाकर रेड्डी, सभी के लिए पीएम किसान सम्मान निधि सहारा बनी है। इन किसानों का कहना है कि इस योजना से छोटे बड़े जमींदारों को सबको बहुत फायदा हुआ है। हर चार महीने में किस्त आ जाती है। इससे उनके घर का और कृषि का सबका काम चलता रहता है। साथ ही, हजार-दो हजार रु. के लिए हर वक्त साहूकार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनकी जरूरतें सम्मान निधि से पूरी हो जाती हैं। पटेल घनश्याम भाई कहते हैं, "बैंक खाते में पैसा आने से बीज, खाद आदि का खर्चा निकल जाता है और समय से खेत में बीज-खाद डाल पाने के कारण उपज अच्छी होती है।"

पीएम किसान सम्मान निधि के ये दो साल भूजोत किसान की मुस्कान के साथ-साथ सशक्तीकरण और सम्मान के हैं, जिसे केंद्र सरकार लगातार बढ़ा रही है। केंद्र से सहायता पाकर देश का किसान खुशियों की फसल उगा रहा है। जबकि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों को रसायनिक ऊर्वरकों से होने वाले नुकसान और भू-जोत की ऊर्वरता बढ़ाने के लिए किस तरह की खाद प्रयोग की जाए, इसकी जानकारी देने में वरदान साबित हो रही है। ●

कैबिनेट के फैसले

जम्मू-कश्मीर की पनबिजली परियोजना का इंतजार खत्म

पहले औद्योगिक विकास को बढ़ावा देनेअगले 15 वर्ष के लिए 28,400 करोड़ रु. की प्रोत्साहन योजना के बाद अब जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में वर्षों से अटकी पनबिजली परियोजना को नया जीवन। इससे इस क्षेत्र में न सिर्फ बिजली का उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने तटवर्ती क्षेत्रों के 30 लाख से ज्यादा कोपरा उत्पादक किसानों को लागत से डेढ़ गुना एमएसपी का दिया तोहफा

फैसला: जम्मू-कश्मीर में समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए 850 मेगावाट की रतले पनबिजली परियोजना के लिए कैबिनेट ने 5281.94 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को दी मंजूरी।

- **लाभ:** जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित परियोजना का निर्माण राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) और जम्मू-कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिडेट की क्रमशः 51 फीसदी और 49 फीसदी की हिस्सेदारी वाली नई संयुक्त उद्यम कंपनी करेगी।
- इस कंपनी में निवेश के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिडेट को भी केंद्र सरकार इक्विटी में योगदान के लिए 776.44 करोड़ रुपये की सहायता देगी। जबकि एनएचपीसी इसके लिए 808.14 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
- इस परियोजना को 60 महीने के भीतर चालू किया जाएगा। इससे जम्मू-कश्मीर में करीबन 4 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा
- जम्मू-कश्मीर को इस परियोजना से 5289 करोड़ की मुफ्त बिजली और 40 वर्षों के प्रोडक्ट लाइफ यानी परियोजना की अवधि के दौरान 9581 करोड़ रुपये के जल उपयोग शुल्क के माध्यम से लाभ होगा।
- इस परियोजना से पैदा होने वाली बिजली से ग्रिड को संतुलन प्रदान करने में मदद मिलेगी और बिजली की आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा।

फैसला: सूखे नारियल की खेती (कोपरा निर्माण) से जुड़े किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी।

- **लाभ:** कोपरा यानी सूखे नारियल के उत्पादन में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है और करीब 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 1.5 करोड़ टन का उत्पादन होता है।
- मिलिंग (पिसाई) कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में लागत के मुकाबले 52 फीसदी की बढ़ोतरी। इसकी लागत 6,805 रु. पड़ती है, लेकिन स्वामीनाथन फॉर्मूले के तहत अब इन किसानों को 375 रु. अधिक यानी 10,335 रु. मिलेगा।
- इसकी अन्य वेराइटी बॉल कोपरा की एमएसपी में लागत के मुकाबले 55 फीसदी की बढ़ोतरी। अब इसके लिए 10,600 रु. मिलेंगे।
- इससे 12 तटवर्ती राज्यों के करीब 30 लाख से ज्यादा किसानों को विशेष लाभ मिलेगा।
- एमएसपी घोषित होने से किसानों को बाजार में भी अधिक कीमत मिलेगी। सरकार की ओर से नाफेड और नेशनल कॉपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन जरूरत पड़ने पर खरीद करेंगे।
- 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ●

आत्मनिर्भरता के रास्ते मिली सफलता

वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही केंद्र सरकार के प्रयास अब धरातल पर उतर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अपने स्टार्टअप के जरिए एक महिला ना सिर्फ पर्यावरण को बचा रही हैं बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं और दूसरों के लिए उदाहरण पेश कर रही है

किसान के लिए ज्यादा लाभ कमाने के खुले रास्ते

किसान रेल जैसी केंद्र सरकार की कृषि को लेकर अहम योजनाएं किस तरह से किसानों के सपने साकार कर रही हैं उसका एक उदाहरण उत्तर प्रदेश के रहने वाले रामगुलाब हैं। सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामगुलाब का जिक्र किया था। रामगुलाब ने शकरकंद की फसल की। उन्हें इसका भाव 15 रुपये प्रति किलो भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब ट्रेन के जरिए रामगुलाब यही शकरकंद अहदाबाद में 25 रुपये/किलो के हिसाब से बेचेंगे। रामगुलाब ने कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) में 300 से अधिक किसानों को जोड़ा है। सब मिलकर खेती कर रहे हैं। फरवरी में फसल तैयार हो जाएगी। पहले किसानों को अपना उत्पाद सड़क मार्ग से बाहर भेजना पड़ता था जिसमें काफी समय और खर्च लगता था। अब रेलवे की मदद से रामगुलाब का शकरकंद कम खर्च और अधिकतम 35 घंटे में गुजरात की मंडियों तक पहुंच जाएगा। इसके लिए किराया 482 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जबकि सड़क मार्ग से इसकी लागत 800 रुपये प्रति क्विंटल पड़ जाता है।●

असम की रूपज्योति कचरे से खड़ा कर दिया ब्रांड

असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए ख्याति प्राप्त है। हर साल पूरी दुनिया से पर्यटक यहां आते हैं। लेकिन काजीरंगा उद्यान के आसपास फेंके जाना वाला कचरा प्रशासन के लिए एक चुनौती बनता जा रहा था। लेकिन स्थानीय निवासी रूपज्योति सैकिया ने अब इस कचरे के निपटारे के साथ उससे कमाई का रास्ता भी ढूंढ निकाला है। वह राष्ट्रीय उद्यान के आसपास फेंके गए प्लास्टिक का कचरा एकत्र करती हैं और उसका कपड़ा बनाती हैं। इस काम में उन्होंने अपने साथ और भी महिलाओं का जोड़ा है। रूपज्योति इस कपड़े का इस्तेमाल परिधान बनाने, स्टोल बनाने, टेबल पर बिछाने सहित अन्य विभिन्न वस्तुएं बनाने में करती हैं। इस कपड़े से बने उत्पादों को 'विलेज वीव' के नाम से बेचा जाता है। असम के 35 गांव की 2,000 से अधिक महिलाएं इस काम से जुड़ चुकी हैं। वर्ष 2012 में उन्होंने 'काजीरंगा हाट' नाम से एक बिक्री आउटलेट भी शुरू किया है।●

"भारत में बना टीका आत्मनिर्भरता और आत्म गौरव का प्रतीक"

कोरोना महामारी से निपटने में भारत दुनिया में सबसे आगे है। अपने 'मन की बात' कार्यक्रम की 20वीं कड़ी में इसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा-'भारत में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और भारत में बना टीका उसकी आत्मनिर्भरता और आत्म गौरव का प्रतीक है।' उन्होंने जमीनी स्तर पर काम करने वालों को पद्म सम्मान देने की कुछ वर्ष पहले शुरू की गई परंपरा का भी जिक्र किया। 26 जनवरी को 72वें गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली के लाल किले में कुछ उपद्रवियों द्वारा तिरंगे के अपमान की घटना का भी उल्लेख किया। पेश हैं 'मन की बात' के अंश:

- स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखें- मैं सभी देशवासियों से आह्वान करता हूं कि वे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, आजादी से जुड़ी घटनाओं के बारे में लिखें। अब , भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष मनाएगा, तो आपका लेखन आजादी के नायकों के प्रति उत्तम श्रद्धांजलि होगी।
- सड़क सुरक्षा माह- इसी महीने 18 जनवरी से 17 फरवरी तक हमारा देश 'सड़क सुरक्षा माह' भी मना रहा है। आज भारत में सड़क सुरक्षा के लिए सरकार के साथ ही व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर कई तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। जीवन बचाने के इन प्रयासों में हमें सबको सक्रिय रूप से भागीदार बनना चाहिए।
- रामायण पर पेंटिंग – कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा जो पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर स्थित 'नया पिंगला' गांव के एक चित्रकार सरमुद्दीन का था। वो प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे कि रामायण पर बनाई उनकी पेंटिंग दो लाख रु. में बिकी।
- 'इंक्रीडेबल इंडिया वीकेंड गेटवे' - पर्यटन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय ने महीने के शुरू में ही बंगाल के गांवों में एक 'इंक्रीडेबल इंडिया वीकेंड गेटवे' की शुरूआत की है।
- 'स्ट्राबेरी फेस्टीवल'- पिछले दिनों झांसी में 'स्ट्राबेरी फेस्टीवल' शुरू हुआ। हर किसी को आश्चर्य होता है 'स्ट्राबेरी फेस्टीवल' और बुंदेलखंड! लेकिन यह सच्चाई है। अब बुंदेलखंड में स्ट्राबेरी की खेती को लेकर उत्साह बढ़ रहा है।
- कचरे से कंचन बनाने की यात्रा - हैदराबाद के बायोनपल्ली में, एक स्थानीय सब्जी मंडी ने तय किया है कि हर रोज बचने वाली सब्जी को ऐसे ही नहीं फेंका जाएगा, इससे बिजली बनाई जाएगी।
- पर्यावरण की रक्षा और आमदनी के रास्ते – पर्यावरण की रक्षा से आमदनी के रास्ते भी खुलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पहाड़ी इलाके में सदियों से 'मोन शुगु' नाम का पेपर बनाया जाता है। इसके लिए पेड़ों को नहीं काटना पड़ता है। ये कागज पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है और स्वास्थ्य के लिए भी।
- स्वच्छता के लिए समर्पण- केरल के कोट्टयम में एक दिव्यांग बुजुर्ग हैं - एन.एस. राजप्पन। वो, पिछले कई सालों से वेम्बनाड झील में जाते हैं और फेंकी गई प्लास्टिक की बोतलें बाहर निकाल कर ले आते हैं। हमें भी, राजप्पन जी से प्रेरणा लेकर, स्वच्छता के लिए योगदान देना चाहिए।
- आप सबसे जुड़ने का अवसर - 'मुझे 'मन की बात' से आप सबसे जुड़ने का अवसर मिलता है। किसी का प्रयास, किसी का जज्बा, किसी का देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून, यह सब मुझे बहुत प्रेरित करते हैं, उर्जा से भर देते हैं।

'मन की बात' पूरी सुनने के लिए QR कोड Scan करें

Narendra Modi @narendram...
#AatmanirbharBharatKaBudget is a Budget for farmers and agriculture sector. It will contribute to the doubling of incomes of our hardworking Annadatas and invigorate the sector with futuristic technologies. Credit availability will improve, APMC apparatus will be

Rajnath Singh @rajnathsingh ·
I specially thank PM& FM for increasing the defence budget to 4.78 lakh cr for FY21-22 which includes capital expenditure worth Rs 1.35 lakh crore. It is nearly19 percent increase in Defence capital expenditure. This is highest ever increase in capital outlay for defence in 15yrs

Amit Shah @AmitShah · 17h
शिक्षा की गुणवत्ता के लिए मोदी सरकार ने ₹3000 करोड़ की राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना शुरू की है। ₹50,000 करोड़ से National Research Foundation शुरू होगा। राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन भी शुरू होगा जिससे क्षेत्रीय भाषाओं के विकास को बल मिलेगा।
#AatmanirbharBharatKaBudget

Nitin Gadkari
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman जी ने जो बजट पेश किया है वो नए भारत की नींव रखेगा और 130 करोड़ भारतवासियों की ज़िंदगी बेहतर करेगा।

Piyush Goyal @PiyushGoyal ·
यह बजट आत्मनिर्भरता के साथ ही देश के प्रत्येक वर्ग, और क्षेत्र में प्रगति की गति को तेज करेगा, तथा नियमों व प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए देश में निवेशकों, व उद्योगों के साथ साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर सैक्टर में सकारात्मक परिवर्तन लायेगा।

Dr Harsh Vardhan @drharsh...
PM श्री @narendramodi जी को जान और जहान दोनों की चिंता है।

#Budget2021 में स्वास्थ्य सेवाओं पर जिस तरह से ज़ोर दिया गया है, वो अभूतपूर्व है।

राजपथ पर पहली बार गरजा राफेल, सेना ने दिखाई शान

परेड में टी-90 भीष्म टैंक, सुखोई, स्वदेशी तेजस ने बिखेरी तेज

हम कोरोना के कई और टीके दुनिया को देंगे : प्रधानमंत्री

सूखे नारियल पर ज्यादा MSP

बजट में आत्मनिर्भरता की दृष्टि, दिल में किसान

"देश में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है और कई प्रावधान किए गए हैं। किसानों को और आसानी से तथा ज्यादा ऋण मिल सकेगा"

भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला बजट

चौतरफा विकास की बात

स्वास्थ्य पर जोर अभूतपूर्व

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कैडेट कोर की रैली में कहा, बीते वर्ष हमने बड़े-बड़े संकटों का सामूहिक शक्ति से सामना किया

देश हर मोर्चे पर अपनी रक्षा में सक्षम : मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा, दिल में हैं किसान और गांव

पहली बार पढ़ा गया पेपरलेस बजट

आर.एन.आई
DELHIN/2020/78812
16 से 28 फरवरी , 2021

न्यू इंडिया
समाचार
पाक्षिक

आरएनआई DELHIN/2020/78812, दिल्ली पोस्टल लाइसेंस नंबर - DL (S)-1/3550/2020-22 डब्ल्यूपीपी संख्या U (S)-98/2020-22, posting at BPC, Meghdoot Bhawan, New Delhi - 110 001 on 13-17 advance Fortnightly
(प्रकाशन तिथि - 4 फरवरी 2021, कुल पृष्ठ-48)

सर्वप्रथम राष्ट्र, फिर गुरु, फिर माता-पिता, फिर परमेश्वर। अत: पहले खुद को नहीं राष्ट्र देखना चाहिए।

-छत्रपति शिवाजी महाराज

19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी की 391वीं जयंती पर नमन

मैं 2014 में पहले रायगढ़ के किले पर गया। छत्रपति जी की समाधि के सामने बैठा, जिस वीर पराक्रमी महापुरुष ने सुशासन और प्रशासन हिंदुस्तान के इतिहास में एक नवीन अध्याय लिखा। अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर संकटों के बीच किया था। संघर्षमय जीवन के रहते हुए किया था। विश्व के इतिहास में ऐसा व्यक्तित्व असंभव है जिसने लगातार संघर्ष के बीच में सुशासन की उत्तम परंपरा को मजबूत बनाया हो और आगे बढ़ाया हो।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री।

संपादक:
कुलदीप सिंह धतवालिया, प्रधान महानिदेशक, पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

प्रकाशक और मुद्रक:
सत्येन्द्र प्रकाश महानिदेशक, बीओसी (ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन)

ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, सूचना भवन, द्वितीय तल, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित

मुद्रण: जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड, बी-278, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-20